सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
YouTube

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 01, अंक 357, नई दिल्ली । बुधवार, 06 मार्च 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

आपको जीवन में इतना मिलेगा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन उससे पहले अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो ।

03 दिल्ली की बकाया 2 सीट से कौन होगा उम्मीदवार ?
06 एमएसपी को कानूनी दर्जे से मजबूत होगी कृषि
08 जिला कलक्टर ने ली विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक

दिल्ली के वाहन मालिकों के लिए एक ऐसी जानकारी जिसका पता होना आपके लिए आवश्यक है, जानें और रखें संभाल कर !

संजय बाटला

नई दिल्ली । दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा यह एक ऐसा आदेश पारित हुआ था जिसकी अधिकतर दिल्ली के वाहन मालिको को जानकारी नहीं होगी पर होनी चाहिए थी। एक आटो चालक द्वारा हमारे अखबार के संवाददाता को बताया कि परिवहन विभाग के आला अधिकारी अपनी इच्छा को ही कानून और नियम मानते हैं और दिल्ली सरकार की आप पार्टी की तरह सिर्फ एक तरफा लोगो के लिए आदेश प्रदान करते हैं जैसे आम पार्टी दिल्ली की महिलाओं के लिए घोषणा करती है वैसे ही परिवहन विभाग के आला अधिकारी सिर्फ उद्योगपतियों के पक्ष में आदेश पारित करते हैं। दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी यह आदेश आपके लिए आपके समक्ष,

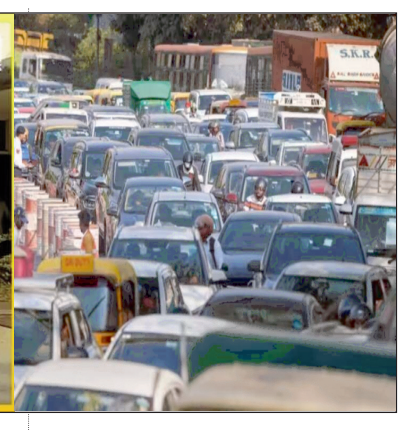

आदेश नम्बरः- 1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
परिवहन विभागः स्क्रैपिंग सेल 5/9, अंडर हिल रोडः दिल्ली -110054

नंबर DC/OPS/2020/153/075645633/7619

दिनांकः 01.01.2024

विषयः-फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण में देरी के कारण विलंब शुल्क से छूट/माफ करने के संबंध में।

कृपया इसके साथ संलग्न आदेश डीसी/ओपीएस/टीपीटी/2021/330/भाग फ़ाइल-II/65724 दिनांक 12.07.2023 देखें, जिसमें सक्षम प्राधिकारी फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण में देरी के कारण विलंब शुल्क के भुगतान से छूट/छूट देता है। वाहन के लिए जो स्क्रैपिंग के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) को जमा करता है। इसे वाहन/आरवीएसएफ पोर्टल पर लागू नहीं किया गया है।

इस संदर्भ में, मुझे आपसे उपरोक्त उल्लिखित आदेश को परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी की वेबसाइट पर अपलोड करने और प्रमाण पत्र के नवीनीकरण में देरी के कारण विलंब शुल्क के भुगतान पर छूट/छूट को लागू करने के लिए एनआईसी के साथ समन्वय करने का अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है। जल्द से जल्द वाहन 4.0/आरवीएसएफ पोर्टल पर फिटनेस की सुविधा।

यह सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से जारी किया जाता है

01/2123.

उप. आयुक्त (स्क्रैपिंग सील)

को, उपायुक्त (आईटी) परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी 5/9, अंडरहिल रोड, दिल्ली-110054

आदेश नम्बरः- 2

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
परिवहन विभागः स्क्रैपिंग सेल 5/9, अंडर हिल रोडः दिल्ली-110054

क्रमांक डीसी/ओपीएस/टीपीटी/2021/330/पार्ट फ़ाइल-II/65724 दिनांकः12/07/2023

आदेश

विषयः-फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण में देरी के कारण विलंब शुल्क से छूट/माफ करने के संबंध में।

दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 37 (ए) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, प्रधान सचिव-सह-आयुक्त, परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार, सक्षम प्राधिकारी होने के नाते, विलंब शुल्क के भुगतान से छूट/छूट देते हुए प्रसन्न हैं। वाहन के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण में देरी के कारण जो स्क्रैपिंग के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) को जमा होता है।

यह एकमुश्त निपटान योजना 01.01.2019 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी। 1 अगस्त 2023.

उप उपायुक्त (स्क्रैपिंग सेल)

क्रमांक डीसी/ओपीएस/टीपीटी/2021/330/पार्ट फ़ाइल-111.65724

दिनांकः12/07/2023

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषितः-

1. पीआर के पीएस। सचिव-सह-आयुक्त (परिवहन), जीएनसीटीडी।
2. सभी विशेष. परिवहन विभाग के आयुक्त, जीएनसीटीडी।
3. सभी उप. परिवहन विभाग के आयुक्त, जीएनसीटीडी।
4. उप. लेखा नियंत्रक, परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी
5. सीनियर सिस्टम एनालिस्ट को परिवहन विभाग की वेबसाइट अपलोड करने हेतु एवं साथ ही

17123.

उपायुक्त (स्क्रैपिंग सेल)

इस आदेश के अनुसार दिल्ली में पंजीकृत वाहन को वाहन मालिक द्वारा स्क्रैप करवाने के लिए वाहन पर लगा जुर्माना या उसकी फिटनेस फीस भी जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है और वाहन मालिक सीधे अपना वाहन आर.वी.एस.एफ. के पास जमा करवा कर वाहन स्क्रैप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते है।

विशेष परिवहन आयुक्त के कथन के अनुसार दिल्ली में व्यवसायिक वाहनों को जारी हो रही है एनओसी

संजय बाटला

नई दिल्ली । आज परिवहन विशेष के मुख्य संपादक दिल्ली के व्यवसायिक वाहन मालिको को दिल्ली स्क्रैप पालिसी की एस.ओ.पी. जारी होने के बाद भी अपने निर्धारित समय सीमा पूरे कर चुके और विभाग द्वारा डी-रजिस्टर किए जा चुके वाहनों की एनओसी प्राप्त करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस बाबत विशेष परिवहन आयुक्त द्वारा वाहन जांच पड़ताल शाखा के अधिकारी से जानकारी ली और उन्हें वहा से बताया गया कि वाहन मालिक के द्वारा वाहन की जीरो फिटनेस मांगने वाले वाहन मालिको को जो वाहन के परमिट जमा करने और एनओसी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जारी कर रहे हैं। आप सभी व्यवसायिक वाहन मालिक जो

अपने समय सीमा पूरे कर चुके वाहनों के परमिट जमा कर एनओसी प्राप्त करना चाहते हैं सीधे वीआईयू बुराड़ी में सीएमवीआई से मिले और अगर आपकों वह जीरो फिटनेस जारी करने से मना करे तो सीधे उनको फोन के माध्यम से विशेष परिवहन आयुक्त शहजाद आलम से बात करने के लिए कहे और अगर जरुरत पड़े तो स्वयं परिवहन मुख्यालय में पहुंचकर विशेष परिवहान आयुक्त से मिलकर अपनी समस्या दर्ज करवा तत्काल हल मांगें।

किसी भी तरह की परेशानी आने पर परिवहन विशेष समाचार के कार्यालय में अपनी बात लिख कर भेजे।

जाम से राहत दिलाने की कवायद शुरू, तीन सड़कें बनाने की प्रक्रिया में आई तेजी

यूपी के गाजियाबाद में हर दिन लाखों लोगों को जाम की झंझट से दो-चार होना पड़ता है। दिल्ली से एलिवेटेड रोड होते हुए आने-जाने वाले लोग रोजाना जाम में फंसकर परेशान होते हैं। ऐसे में अब प्राधिकरण ने जाम की झंझट से राहत दिलाने की कवायद शुरू कर दी है। जमीन लेने के लिए किसानों के साथ अगली बैठक 12 मार्च को होगी।

गाजियाबाद। दिल्ली से एलिवेटेड रोड होते हुए राजनगर एक्सटेंशन, मुरादनगर, मोदीनगर व अन्य स्थानों पर आने-जाने वाले लाखों लोग रोजाना जाम में फंसकर परेशान होते हैं। लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जीडीए ने कवायद शुरू कर दी है। इस कड़ी में मंगलवार को प्राधिकरण सभागार में जीडीए अधिकारियों व किसानों की बैठक हुई।

जमीन न मिलने से अटका काम : किसानों ने जमीन देने के रजामंदी दे दी है। नादर्न पेरिफेरल रोड, राजनगर एक्सटेंशन आउटर रिंग रोड व मिगसन सोसायटी के सामने जोनल प्लान की रोड जो वर्तमान में जमीन न मिलने के कारण अटकी पड़ी है। उक्त सड़कों में किस किसान की कितनी जमीन आ रही है। इसके लिए प्राधिकरण का भू-अर्जन अनुभाग रिकॉर्ड खंगालकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसके बाद जमीन लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

12 मार्च को किसानों के साथ बैठक : जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में किसानों का रूख सकारात्मक रहा। अब प्राधिकरण अपने स्तर से कार्रवाई शुरू करेगा। किसानों के साथ अगली बैठक 12 मार्च को होगी। मालूम हो कि उपरोक्त तीनों सड़कों में 3646 वर्गमीटर जमीन किसानों की आ रही है। जीडीए के मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह ने बताया कि नादर्न पेरिफेरल रोड के लिए मोरटा गांव की 787 वर्गमीटर, राजनगर एक्सटेंशन आउटर रिंग रोड के लिए मोरटा गांव की 160 वर्गमीटर, शाहपुर गांव की 430 वर्गमीटर, अटौर गांव की 290 वर्गमीटर, मोरटी नूरनगर गांव की 500 वर्गमीटर और 45 मीटर चौड़ी रोड के लिए सिकरोड गांव की 900 वर्गमीटर व मोरटा की 559 वर्गमीटर जमीन ली जानी है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के व्यवसाय में जुड़े सभी व्यापारियों के लिए निमंत्रण

भारत के अग्रणी क्रेडिट और कलेक्शन सॉफ्टवेयर, रिकॉर्डेंट के सहयोग से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन (आई.एफ.ई.वी.ए.) द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित बंद-दरवाजा कार्यक्रम

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारत के अग्रणी क्रेडिट और कलेक्शन सॉफ्टवेयर, रिकॉर्डेंट के सहयोग से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन (आई.एफ.ई.वी.ए.) द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित बंद-दरवाजे कार्यक्रम के लिए आपको निमंत्रण देते हुए खुशी हो रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 2-3 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्षेत्र में एसएमई की प्रतीक्षा में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पड़ताल करना है।

कार्यक्रम की जानकारी:

दिनांक: 9 मार्च, 2024

समय: दोपहर 2:45 बजे से शाम 6:30 बजे तक

कार्यक्रम का स्थान:-

लघु उद्योग भारती, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली

हमारा मानना है कि आप सब की भागीदारी आयोजन की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देगी आपका अद्वितीय दृष्टिकोण और अनुभव चर्चा को बढ़ाएगा और उद्योग के पेशेवरों के बीच एक सहयोगात्मक माहौल को बढ़ावा देगा। इवेंट के लिए पंजीकरण करने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

https://forms.zohopublic.com/recordent/form/EventRegistration/formperma/Qp9TqSc4lV8Z5zQzGveUdE9yftwcxhiWC4BG_PVOxk0

कृपया ध्यान दें कि पंजीकरण केवल सीमित समय के लिए खुले हैं, इसलिए हम आपको तुरंत अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम उत्सुकता से आपकी सक्रिय भागीदारी की आशा करते हैं।

साभार, आईएफईवीए टीम

ओला कैब ड्राइवर से सावधान, पर्दाफाश करतूत- 3

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। ओला कैब ड्राइवर्स की करतूतों का पर्दाफाश करने की कडी में अखबार के पाठकों में शुमार तीन अन्य पीडित महिलाओ का भी दर्द छलक उठा। वह आगे बढकर सामने आ गई। उन्होंने भी अपने दर्द भरे खौफनाक वाक्य को अखबार से शेयर किया है। रोहिणी निवासी पिडीता महिला सुरभि के मुताबिक 19 मार्च, 2021 की शाम करीब 4-5 बजे अपनी मां रजनी ,भाभी और उसके 3 महीने के नन्हें बच्चे को शास्त्री नगर स्थित एक क्लिनिक पर बीमार भतीजे को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गई थीं। पीडित सुरभि के मुताबिक वापस रोहिणी घर लौटने के लिए ओला की गाडी बुक की। बकौल सुरभि गाडी में हम तीनों बैठे और ड्राइवर ने रवानगी डाल दी। इन्द्रलोक मैट्रो स्टेशन के पास पहुंचकर वह नशे की हालत में झुमते हुए गाडी चला रहा था। साथ ही वह चलती गाडी में बार-बार नीचे झुक कर अजीब -अजीब सी हरकते करने लगा। इस बात से डर कर कहीं कोई हादसा ना कर दे। उसको चेताया भाई शराब के नशे में गाडी क्यों चला रहे हो। गाडी रोको।वह उसी वहशी हरकतों के साथ गाडी चलाता रहा। बकौल मां रजनी ने चीख कर ड्राइवर से गाडी रोकने को कहा। ड्राइवर अपनी गंदी हरकत और नशे में वैसे ही गाडी को जिक-जैक करता रहा। मां रजनी के मुताबिक जब चिल्ला कर पुलिस को फोन करने का डर दिखाकर ड्राइवर को गाडी बकौल पीडिता सुरभि ने जबरन रोकने को कहा। तो ड्राइवर ने अनमने मन से गाडी रोक दी। हम तीनों नन्हें बच्चे को गोदी में उठाए जल्दी से गेट खोलकर गाडी से उतर गए। पीडिता मां रजनी के मुताबिक ड्राइवर हमसे जबरदस्ती पूरे पैसे वसूलने की जिद पर अढने लगा। नशे में ड्राइवर के ज्यादा झगड़ने की सूरत में शास्त्री नगर से इन्द्रलोक

तक जाने के लिए जैसे-तैसे उसे सौ रूपये थमा कर अपनी जान छुडाई। बकौल पीडिता सुरभि ने बताया कि हालांकि ड्राइवर की हरकत अधूरे सफर का पूरा किराया वसूलने की बावत ओला कस्टमर्स हेल्प लाइन पर कंपलेंट भी कर दी। लेकिन आजतक पता नहीं ड्राइवर के खिलाफ ओला कंपनी ने कोई एक्शन लिया या नहीं इसकी कोई सूचना तक नहीं दी गई। उस वक्त के नशे की हालत में डरावने ओला के ड्राइवर के साथ सफर की सिहरन आज भी ताजा है। पीडिता ने इस संवाददाता को बताया कि यकीन मानिये हमने उस खौफनाक मंजर के बाद ओला की गाडी को बुक तक नहीं किया। यहां तक कि ओला ड्राइवर के साथ हुए कडवे अनुभव से ओला ऐप को ही मोबाइल से डिलीट कर दिया है।

द्वारका एक्सप्रेसवे को 9,000 करोड रुपए की लागत से बनाया गया है

द्वारका एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हो जाएं तैयार 11 मार्च को होगा उद्घाटन..

द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 स्टेज में किया जा रहा है। जिसमें से पहला पैकेज दिल्ली महिपालपुर के शिव मूर्ति से बिजवासन तक, दूसरा बिजवासन आरओबी से गुरुग्राम में दिल्ली हरियाणा सीमा तक, तीसरा पैकेज बसई आरओबी तक और चौथा पैकेज बसई आरओबी से खेड़की दौला तक है। द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली और गुड़गांव को जोड़ने वाला तीसरा सीधा रास्ता होगा, जो कि पहले से मौजूद दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे और दिल्ली महरौली रोड गुरुग्राम के बाद बनाया जा रहा है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। द्वारका एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम वाले हिस्से का उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 मार्च को इसका उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे को 9,000 करोड रुपए की लागत से बनाया गया है। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेनियम सिटी में 18 किलोमीटर लंबा रोड शो पहली बार करेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब मिलेनियम सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे।

गुरुग्राम और दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी बेहतर-

इस कार्यक्रम को लेकर गुरुग्राम पुलिस और जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को रेवाड़ी में गुरुग्राम मेट्रो विस्तार परियोजनाओं का शिलान्यास किया था।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उपायुक्त निशांत कुमार यादव और पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने द्वारका एक्सप्रेसवे का दौरा कर तैयारी का जायजा लिया है और उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होने से गुरुग्राम और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी।

निर्माण 4 स्टेज में-

द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 स्टेज में किया जा रहा है। जिसमें से पहला पैकेज दिल्ली महिपालपुर के शिव मूर्ति से बिजवासन तक, दूसरा बिजवासन आरओबी से गुरुग्राम में दिल्ली हरियाणा सीमा तक, तीसरा पैकेज बसई आरओबी तक और चौथा पैकेज बसई आरओबी से खेड़की दौला तक है।

द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली और गुड़गांव को जोड़ने वाला तीसरा सीधा रास्ता होगा, जो कि पहले से मौजूद दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे और दिल्ली महरौली रोड गुरुग्राम के बाद बनाया जा रहा है।

29 किलोमीटर लंबा-

यह एक 16 लेन वाला हाईवे है, जिसे हाई स्पीड गाड़ियों के लिए बनाया गया है। रास्ते में किसी भी तरह का ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, यह एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर लंबा है। जिसमें चार बहु स्तरीय इंटरचेंज बिना सिग्नल वाला हाईवे है। इंजीनियर के चमत्कार में मोटोरवे के दोनों और तीन लेन की सर्विस लेन होगी। बहु स्तरीय इंटरचेंज और प्रमुख जंक्शनों पर कई सब-वे बनाए जाएंगे। गुरुग्राम मानेसर शहरी परिषद के विकास के लिए द्वारका पर एक्सप्रेसवे के साथ एक मानसरोवर ट्रांज़िट सिस्टम की योजना भी बनाई गई है।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

इनसाइड

30 की उम्र में महिलाएं खाएं ये कैल्शियम पैक्ड होममेड लड्डू, हड्डियां नहीं होंगी कमजोर, पीरियड्स का दर्द भी भूल जाएं

महिलाएं अक्सर घर और ऑफिस के कामों में खुद की सेहत, खानपान, लाइफस्टाइल का ध्यान देना भूल जाती हैं. ऐसे में 30-35 की उम्र में ही हड्डियों, मांसपेशियों, बाल, त्वचा से संबंधित समस्याओं से परेशान रहने लगती हैं. आए दिन कभी शारीरिक कमजोरी, खून की कमी, थकान, सुस्सी, पेट दर्द, कमर दर्द झेलती रहती हैं. परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसा एक बेहद ही हेल्दी और पौष्टिक लड्डू की रेसिपी, जिसे आप खाकर कई तरह की छोटी-मोटी समस्याओं को खुद से दूर रख सकती हैं. ये लड्डू स्पेशली 30 की उम्र वाली महिलाओं के लिए है. न्यूट्रिशनिस्ट जूही कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसकी रेसिपी शेयर की है और फायदे भी बताए हैं. इस लड्डू का नाम है अमरंथ तिल लड्डू (Amaranth Sesame Ladoo). इसे अमरंथ और तिल से बनाया गया है. अमरंथ और तिल दोनों ही बेहद हेल्दी होते हैं.

अमरंथ तिल लड्डू बनाने के लिए सामग्री
पफ्ड अमरंथ- 4 बड़ा चम्मच
बादाम (भुने और कटे हुए)- 4 बड़े चम्मच
तिल भुने हुए- 2 बड़े चम्मच
ककाओ पाउडर- 1 बड़ा चम्मच (cacao powder)
खजूर- 15-20

अमरंथ तिल लड्डू बनाने की विधि
अमरंथ को आप चाहें तो हल्का रोस्ट भी कर सकती हैं. तिल भी आप भून लें. बादाम को भी रोस्ट करके काट लें. खजूर को पीसकर पेस्ट बना लें. इसमें अन्य सामग्री जैसे अमरंथ, तिल, कटे हुए बादाम डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें. इसे गोल-गोल आकार में लड्डू की तरह शेप दे दें.

अमरंथ तिल वाले लड्डू खाने के फायदे
इस लड्डू में कैल्शियम भरपूर मात्रा में है. इसे आप अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकती हैं. हड्डियों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है. पीरियड्स साइकिल इर्रेगुलर रहता है, क्रैम्प, दर्द से परेशान रहती हैं, तो आप ये लड्डू जरूर खाएं. यह स्किन की समस्याओं को भी दूर रखता है. त्वचा हेल्दी रहती है, ग्लो आता है. Premenstrual syndrome से लड़ने में बेहद कारगर है. यदि आप इन सभी समस्याओं से जूझ रही हैं तो आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके जरूर देखें.

पीरियड क्रैंप को रोकने के लिए लेती हैं पेनकिलर मेडिसिन?

मासिक धर्म के दौरान क्रैंप होना आम समस्या है. यह ऐंठन और दर्द पीरियड शुरू होने से एक दिन पहले से लेकर शुरू होने के दो दिन बाद तक अनुभव हो सकता है. इस दर्द की वजह से ना केवल महिलाओं के लिए उठना बैठना या सामान्य काम करना मुश्किल भरा हो जाता है, साथ ही यह मेंटल हेल्थ को भी काफी प्रभावित करता है. ऐसे में महिलाएं दर्द और क्रैंप को कंट्रोल करने के लिए ओवर द काउंटर पेन किलर का इस्तेमाल कर लेती हैं. इससे कुछ देर के लिए दर्द से राहत तो मिल जाता है लेकिन क्या यह लॉन्ग टर्म के लिए महिलाओं के लिए परेशानी का कारण बन सकता है ! तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियां.

पीरियड कैंप या दर्द की वजहें
एनएचएस के मुताबिक, दरअसल मासिक धर्म में दर्द तब होता है जब मासिक धर्म के दौरान एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस बढ़ जाता है. गर्भाशय के अंदर और आसपास फाइब्रॉएड की मात्रा बढ़ जाती है, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय में संक्रमण जैसी समस्या हो जाती है या कई बार इंट्रायूट्रिन डिवाइस यानी आईयूडी भी मासिक धर्म में दर्द का कारण बन सकता है. खासकर अगर इसे 3 से 6 महीने पहले ही लगवाया गया है.

पीरियड क्रैम्प का इलाज
अगर आपके पीरियड के दौरान असहनीय दर्द महसूस हो रहा है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें. आप इससे बचने के लिए नेप्रोक्सेन, फ्लर्बिप्रोफेन या मेफेनैमिक एसिड जैसी एंटी इंफ्लोट्री दवाओं का सेवन कर सकती हैं. ये दवाइयां बिना डॉक्टरों की सलाह नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए कोई भी दवा बिना डॉक्टरों की सलाह न लें।

प्राणायाम को साधकों की दिव्य शक्ति' किंतु कैसे ?

प्राण का अर्थ है- ऐसा जीवन तत्व जो ब्रह्माण्ड के साथ ही साथ मानव शरीर में भी व्याप्त है। इस प्राण के माध्यम से ही मानव का इस ब्रह्माण्ड से अटूट सम्बन्ध है। प्राण को दूसरे रूप में जीवन कहा गया है। यदि प्राण बंद हो जाते हैं तो यही समझा जाता है कि जीवन समाप्त हो गया है। प्राण की व्याख्या करते हुए शास्त्रों में लिखा है- **"प्राण यति जीव यति इति प्राण"** अर्थात जो प्राणी मात्र के जीवन का आधार बन कर रहता है वह प्राण है।

प्राण को नियमित रूप से संचालित करने को प्राणायाम कहा गया है। इसके माध्यम से चंचल और उच्छृंखल मन निर्दिष्ट केन्द्र पर स्थिर होना सीखता है, और जीवन एक सही रूप में नियमित होता है। श्वास की गति में तीव्रता होने से जीवन का शक्ति-कोष जल्दी समाप्त हो जाता है,

खरगोश प्रति मिनट ३८ बार श्वास लेता हैं और उसकी आयु ८ वर्ष होती है।
कबूतर श्वास प्रति मिनट ३७, आयु ८ वर्ष।
कुत्ता श्वास प्रति मिनट २८, आयु १३ वर्ष।
बकरी श्वास, प्रति मिनट २४, आयु १४ वर्ष।
मनुष्य श्वास प्रति मिनट १२, आयु १०० वर्ष।
हाथी श्वास प्रति मिनट ११, आयु १०० वर्ष।
कछुआ श्वास प्रति मिनट ४, आयु १५० वर्ष।

इस तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रति मिनट जितनी कम श्वास ली जाती है उसकी आयु १५-१६ तक पहुँच गई है। इसी अनुपात से उसकी आयु भी घट गई है। जब श्वास की गति बढ़ती है तो तापमान भी बढ़ जाता है। यह बढ़ा हुधा तापमान आयु क्षय करता है। **प्राणायाम में गहरी और लम्बी श्वांस लेने का अभ्यास किया जाता है।** यह अभ्यास व्यक्ति के सामान्य समय में भी हो जाता है अर्थात प्राणायाम का अभ्यास करने वाला व्यक्ति सामान्य जीवन में भी लम्बी और गहरी श्वास लेने का अभ्यस्त हो जाता है। ऐसा होने पर उसका दीर्घ जीवी होना स्वाभाविक है। गहरी श्वास लेने से फेफड़े ही नहीं अपितु पाचन संस्थान भी परिपुष्ट बनता है। इससे मनुष्य अधिक कार्य करने की क्षमता अपने आप में प्राप्त कर सकता है। और २५९२० बार पूरी हवा अन्दर समाहित करने से उसमे विशेष शक्ति, तेजस्वीता और तारूण्य का संचार होता है। इसका प्रभाव मस्तिष्क पर भी पड़ता है और इससे स्मरण शक्ति की वृद्धि होने के साथ साथ दिन भर मनुष्य तरौ ताजा बना रहता है. प्राणायाम को देती शक्ति भी कहा गया है।

खींचने को पूरक,
रोकने को कुम्भक, तथा छोड़ने को रेचक कहा जाता है। पर इससे हीं सब कुछ सभव नहीं है यह एक विशेष विधि है और गुरु के द्वारा ही इस विधि की सुक्ष्मता को भली प्रकार से समझा जा सकता है।

प्राणायाम के अनेको भेद हैं। सामान्यतः ८४ प्राणायामों की चर्चा है, **इनमें से शीतली, सीत्कारी, उज्जायी, भस्त्रिका आदि आठ नक्ष प्राणायाम हैं,** इन सब के अलग अलग विधान तथा परिणाम हैं। पर यह निश्चित है कि इस प्रकार नियम पूर्वक प्राणायाम करने से शरीर के रोम रोम में प्राण तत्व भर जाते हैं और शरीर सुन्दर, सजीला, बलिष्ठ, तेजस्वी तथा संकल्पयुक्त बन जाता है।

प्रारंभिक आठ प्रकार के प्राणायाम का अभ्यास हो जाने के बाद प्राण प्रवाह क्रिया सीखी जा सकती है क्योंकि **शरीर में प्राण प्रवाह की दस धाराएं मानी गई है,** प्रत्येक श्वास के साथ हम आकाश से हवा ही नहीं अपितु आकाश विद्युत भी खींचते हैं। यह विद्युत एक विशेष चेतना युक्त होती है जिसे ईश्वरीय प्रवाह कहा गया है। ऐसा अभ्यास होने पर मानव ईश्वरीय सदेशों को भी सुन सकता है, देख सकता है और समझ सकता है। प्राणायाम हमें समस्त ब्रह्माण्ड की उन सूक्ष्म तरंगों से सम्बन्ध कर सकता है जिसके माध्यम से विश्वव्यापी हलचले होती है और इस प्रकार की विश्व व्यापी तरंगों से सम्बन्ध होने पर सुदूर घटित घटनाओं को हम प्राणायाम के माध्यम से अनुभव कर सकते है। **मोटे तोर पर नाक के श्वास खीचने की, रोकने की तथा छोड़ने की विशेष विधि को प्राणायाम कहते हैं।**

प्रारंभिक आठ प्रकार के प्राणायाम का अभ्यास हो जाने के बाद प्राण प्रवाह क्रिया सीखी जा सकती है क्योंकि **शरीर में प्राण प्रवाह की दस धाराएं मानी गई है।** जिनमें पांच नाभी प्रदेश से ऊपर की और उठती है तथा पांच नीचे की और बहती हैं। **ऊपर की और उठने वाली धाराधों को ऊर्ध्वगामी प्रवाह कहा जाता है।** महत्व की दृष्ट्रि से यह विशेष महत्वपूर्ण है और प्राणायाम की विशेष विधि से प्राणों को ऊर्ध्वगामी बना कर कुण्डली जाग्रत की जाती है।

प्राणायाम प्रत्येक साधक गृहस्थ के लिये आवश्यक अंग है। इसके द्वारा हमारा स्थूल शरीर आरोग्य वान बनता है, सूक्ष्म शरीर में एकाग्रता पवित्रता तथा संतुलन आता है और इन दोनों शरीरों के समानुपातिक अभ्यास कई सिद्धियों और विभूतियों का द्वार खोल देता है जिससे कि मानव इन चर्म चक्षुओं से भी देवत्व के दर्शन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर पाता है।

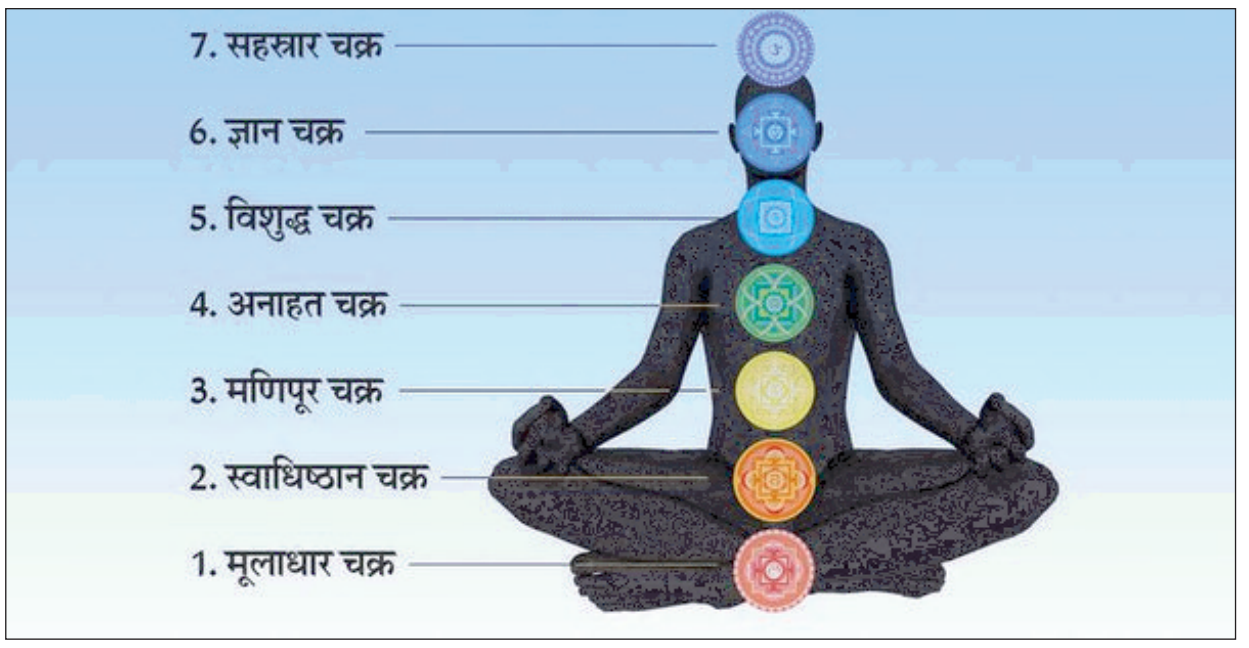

दिन को सफल बनाने वाले पांच सूत्र !

हमारे सनातन ग्रंथो में बेहतर जीवन शैली जीने के कई तरीके बताएं गए हैं। हमारे ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति की दिनचर्या में कुछ बातों का होना अतिआवश्यक है। सुबह की शुरुआत में कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए, आज जानते हैं सुबह किन 5 बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

स्नानं दानं होमं स्वाध्यायो देवतार्तनम्।
यस्मिन्दिने न सेव्यन्ते स वृथा दिवसो नृणाम्।।

1. स्नान-:
स्नान मनुष्य की दिनचर्या का सबसे अहम हिस्सा है। धार्मिक पुराणों के अनुसार दिन की शुरुआत स्नान से ही होनी चाहिए। सुबह सबसे पहले स्नान करके पवित्र होने से पूरा दिन अच्छा जाता है और दिनभर ऊर्जा का संचार होता रहता है।
स्नान प्राय सुबह सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए, स्नान करते समय पवित्र नदियों का मानसिक ध्यान करें।

2. दान-:
कई धर्म-ग्रंथों और पुराणों में दान के महत्व के बारे में बताया गया है। व्यक्ति को अपनी श्रद्धा के अनुसार रोज कुछ न कुछ दान करना चाहिए। ऐसा करने से धन-धान्य की कमी नहीं होती है और घर में सुख-शांति का माहौल बना रहता है।अपनी सामर्थ्य अनुसार दान जरूर करें।
दान के रूप में आप पक्षियों को दाना और गाय को गुड़-हरा चारा इत्यादि प्रतिदिन अवश्य खिलाना चाहिए और जरूरतमंद असहाय व्यक्तियों की मदद करें।

3. हवन या दीपक जलाना-:
घर की सुख-शांति के लिए हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हर किसी को अपनी दिनचर्या में हवन करने को शामिल करना चाहिए। रोज हवन नहीं कर पाएं तो भगवान और तुलसी के समक्ष गाय के घी का दीया अवश्य जलाएं।

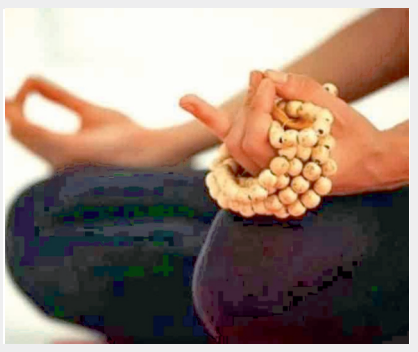

4. जप-:
हमारी मान्यताओं के अनुसार पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए जप से बहुत अधिक फायदा मिलता है। मनुष्य को जप करने का शुभ फल जरूर मिलता है, अतः कुछ समय अपने गुरु मंत्र या फिर इष्ट मंत्र का जप करें।

5. देव पूजन-:
सुबह स्नान करने के बाद भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के बाद भगवान को भोग भी लगाना चाहिए। नित्य नियम से पूजा करने से घर-परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहती है। अतः रोज पूजा करने का नियम अवश्य बना लें।।

यह सनातन संस्कृति के कुछ सामान्य नियम है अतः अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में से कुछ समय इन छोटी-छोटी बातों के लिए जरूर निकले, विश्वास कीजिए ऐसा करने से आपके जीवन में सुख- शांति व आत्म संतोष बना रहेगा।।

ग्रहों का गोचर

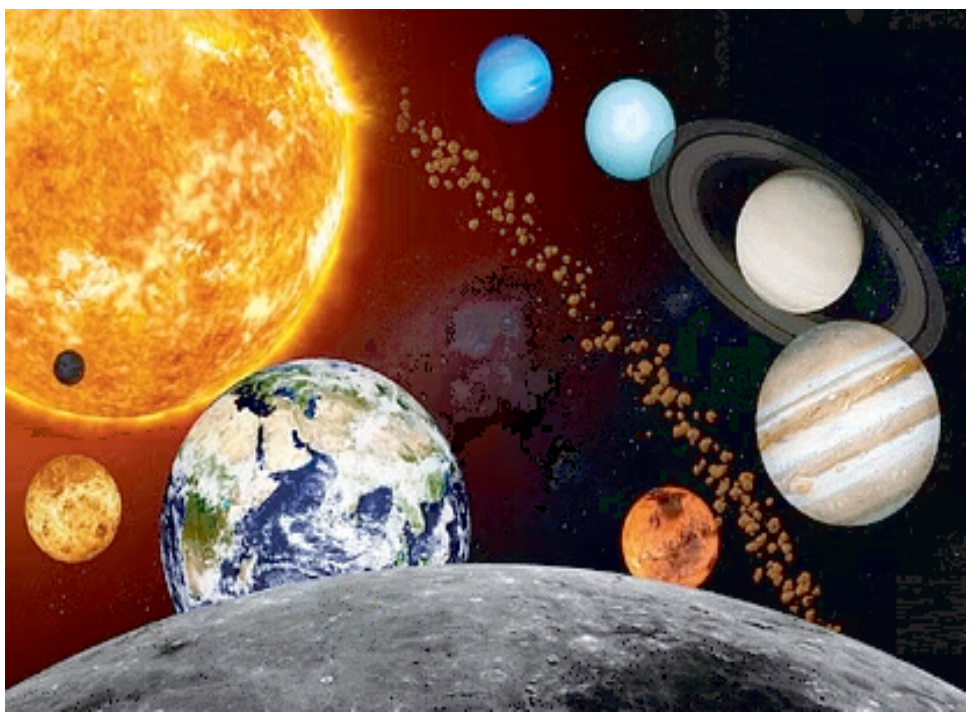

ज्योतिष विज्ञान के अनुसार, ब्रह्माण्ड में विचरण कर रहे सभी खगोलीय पिंड का प्रभाव प्रकृति, पृथ्वी और यहां रहने वाले सभी जीवों पर अलग-अलग प्रकार से पड़ता है। साथ ही यह भी बताया गया है कि सभी ग्रह एक व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं और इनका प्रभाव सभी राशियों पर सकारात्मक व नकारात्मक रूप से पड़ता है। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य है, इसके बाद उपग्रह चंद्रमा है। वहीं शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति और शनि ग्रह भी अहम योगदान देते हैं। इसमें से दो ग्रह अर्थात राहु और केतू को पापी या छाया ग्रह माना जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह सभी ग्रह एक अवधि के बाद ग्रह गोचर, वक्री, नक्षत्र परिवर्तन, उदय और अस्त होते हैं। ग्रहों की इन स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों पर सकारात्मक व नकारात्मक रूप से पड़ता है।

ग्रह गोचर क्या होता है..?
ज्योतिष शास्त्र में गोचर को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गोचर को दूसरी भाषा में राशि परिवर्तन भी कहा जाता है। जब एक ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे ग्रह गोचर या राशि परिवर्तन कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में नौ ग्रहों का वर्णन किया गया है। वे नौ ग्रह हैं- सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। यह सभी ग्रह एक निश्चीत अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों के स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, कार्यक्षेत्र आदि पर पड़ता है।

प्रत्येक ग्रह के गोचर की समयावधि-:
एक ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में अपने निश्चित समय अवधि में परिवर्तन करते हैं जैसे-: सूर्य एक माह के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। वहीं, चंद्र गोचर करने में सवा दिन लेते हैं। मंगल करीब डेढ़ महीने के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, वहीं एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए बुध 14 दिन और देव गुरु बृहस्पति एक साल का समय लेते हैं। शुक्र ग्रह को राशि परिवर्तन में 23 दिन लगता है और शनि देव ग्रह गोचर में सबसे अधिक ढाई साल का समय लेते हैं। छाया ग्रह राहु और केतु राशि परिवर्तन में डेढ़ साल का समय लेते हैं।

ग्रहों का उदय और अस्त क्या होता है..?
ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सूर्य ग्रहों के राजा है और इनका प्रभाव न केवल राशियों पर लेकिन ग्रहों की स्थिति पर भी पड़ता है। बता दें कि जब कोई ग्रह सूर्य के इतना निकट चला जाता है कि उनके तेज से ग्रह पूर्ण रूप से प्रभावहीन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ग्रह को 'अस्त ग्रह' कहा जाता है। ऐसी स्थिति में ग्रह का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अस्त होने का दोष सूर्य के अलावा सभी ग्रहों पर लगता है। वहीं जब ग्रह सूर्य से निश्चित दूरी बना लेते हैं, तब उन्हें 'उदित ग्रह' या ग्रह उदय कहा जाता है। ग्रहों के उदय होने से शुभ फलों की प्राप्ति पुनः प्रारंभ हो जाती है।

मार्च माह में ग्रहों का गोचर-:
इस माह मार्च 2024 में कई ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे जिसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। 07 मार्च 2024 को बुध ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे। 07 मार्च को ही शुक्र ग्रह कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 14 मार्च को सूर्य का मीन राशि में गोचर होगा और 15 मार्च को मंगल ग्रह का कुंभ राशि में गोचर होगा। और इसी माह में जो शनि देव अस्त चल रहे थे वे 18 मार्च को कुंभ राशि में उदय होंगे। ग्रहों का यह गोचर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव देखने को मिलेगा।

कैंसर बढ़ रहा है क्योंकि, आख़िरकार सच सामने आ गया.

बड़े पैमाने पर ट्यूमर का प्रकोप आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों से संबंधित है ! यह एक निर्णायक परिवर्तन है: सुपरमार्केट में जाते समय हर किसी को ध्यान से पढ़ना चाहिए:
₹४₹ से शुरू होने वाले बारकोड आनुवंशिक रूप से संशोधित उत्पाद हैं ! कोई फर्क नहीं पड़ता कि विशेषज्ञ इस बात की कितनी वकालत करते हैं कि आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ हानिरहित हैं, हमें निम्नलिखित दस बातें याद रखनी चाहिए:

1. अमेरिकी इसे नहीं खाते.
2. ई.यू. इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाता है।
3. चीनी अधिकारियों के लिए विशेष रूप से ऐसा भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था सख्त वर्जित है।
4. वर्ल्ड एक्सपो में जीएमओ से उगाए गए खाद्य पदार्थ सख्त वर्जित हैं।
5. एशियाई खेलों में भी इन्हें सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है
6. अफ्रीकी लोग जीएमओ का आयात नहीं करेंगे, भले ही वे भूखे मर जाएं।
7. विश्वविद्यालयों में इनका सख्त निषेध है।
8. रूस ने पुष्टि की है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित भोजन तीन पीढ़ियों के लिए जानवरों के विलुप्त होने का कारण बना है।
9. वे कृषि मंत्रालय के किंडरगार्टन में निषिद्ध हैं।
10. वित्त मंत्रालय की कैंटीन में इन्हें प्रतिबंधित किया गया है.

आयातित फल खरीदते समय लेबल स्पष्ट रूप से पढ़ें:
8 से शुरू होने वाले 5-अंकीय कोड आनुवंशिक रूप से संशोधित उत्पाद हैं। उन्हें मत खरीदो।₹ आयातित फलों पर लगे लेबल को पीएलयू कोड कहा जाता है। उपयोग किए जाने वाले चार अंकों के कोड आम तौर पर ₹3₹ और ₹4₹ से शुरू होते हैं, और यह दर्शाता है कि फसल पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके उगाई गई है; यदि यह पाँच अंकों का है और ₹9₹ से शुरू होता है, तो यह जैविक है; यदि यह ₹8₹ से शुरू होता है, तो यह आनुवंशिक रूप से होता है संशोधित.
कृपया ध्यान दें कि अपनी भलाई के लिए आपको खुद को खाद्य स्वच्छता ज्ञान के बारे में शिक्षित करना होगा और सरकार या उद्यमों पर निर्भर नहीं रहना होगा !
प्यार की यह डोर आपके हाथों में !

दिल्ली की बकाया 2 सीट से कौन होगा उम्मीदवार ?

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी कर दी ।भाजपा की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 195 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान कर दिया गया है। पहली लिस्ट में दिल्ली की 7 में से 5 सीटों के लिए उम्मीदवार के नाम है। लेकिन दिल्ली की 2 सीटों पर बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। जिन 2 सीटो के लिए भाजपा का ऐलान बाकी है, उनमें क्रिकेटर से राजनेता बने गोतम गंभीर की सीट ईस्ट दिल्ली और सूफी गायक हंसराज हंस की सीट नार्थ वेस्ट दिल्ली शामिल है।

हालांकि गोतम गंभीर ने गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए कहा कि मुझे राजनीतिक दायित्वों से मुक्त करें। अब इनकी जगह पर दो नामों की चर्चा खास है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा टिकट की रेस में आगे बताए जा रहे हैं।

दूसरी ओर केजरीवाल ने यहीं से दलित दांव खेलते हुए आम आदमी पार्टी ने जनरल सीट से एससी को इस सीट से विधायक कुलदीप कुमार को उम्मीदवार बनाया है। कुलदीप कुमार एक सफाई कर्मचारी के बेटे हैं और दलित बिरादरी से आते हैं। जबकि नार्थ वेस्ट दिल्ली की सीट एससी के लिए रिजर्व है। इस सीट से फिलहाल दलित सांसद सूफी गायक हंसराज हंस हैं। इस बार इनका टिकट काट दिया गया है। इनकी जगह पर योगेन्द्र चंदौलिया को टिकट मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी दलित नेता की फेहरिस्त में पूर्व सांसद उदित राज और कृष्णा तीर्थ के नाम मजबूत दावेदारों में शुमार हैं। बहरहाल बीजेपी इन बाकी बची दो सीटों पर रणनीति के तहत माथा पच्ची कर रही है। दरअसल भाजपा का नार्थ वेस्ट दिल्ली सीट का पिछला अतीत देखें तो हर चुनाव में नया चेहरा संसद की चौखट चढता है। बता दें कि साल 2008 के परिसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आई थी। साल 2009 में यहां पहली बार चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस की कृष्णा तीर्थ को जीत मिली थी ।इसके बाद 2014 में बीजेपी के टिकट पर उदित राज जीतकर संसद पहुंचे। वर्तमान में उदित राज कांग्रेस में ताल ठोक रहे हैं।

घर नाम नहीं कराया तो पति ने दिव्यांग पत्नी को जिंदा जलाया, बेटी ने पुलिस के सामने खोला राज

मृतका दिल्ली नगर निगम स्कूल में शिक्षिका थी। आरोपी पति ने पहले पुलिस को गुमराह करने के लिए गैस पाइपलाइन से रिसाव के कारण आग लगने की झूठी कहानी गढ़ी ।मामले में पुलिस ने पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस आग में आरोपी पति भी झुलस गया है जिसका अस्पताल में इलाज जारी है।

दिल्ली। बेगमपुर थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह पति ने अपनी पत्नी पर केरोसिन तेल छिड़ककर आग लगा दी। जिससे महिला बुरी तरह से झुलस गई। आनन-फानन में महिला को पास के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां महिला की मौत हो गई।

मृतका दिल्ली नगर निगम स्कूल में थी अध्यापिका

मृतका दिल्ली नगर निगम स्कूल में शिक्षिका थी। आरोपी पति ने पहले पुलिस को गुमराह करने के लिए गैस पाइपलाइन से रिसाव के कारण आग लगने की झूठी कहानी गढ़ी। लेकिन, दपंती की 12 वर्षीय बेटी ने पुलिस को बताया कि उनके पिता ने ही उनकी मां को जिंदा जलाकर मार डाला।

वारदात में दोनों बेटियां व आरोपी भी झुलसा

इस मामले में पुलिस ने पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस आग में आरोपी पति भी झुलस गया है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त गुरइकबाल सिंह ने बताया कि बीते सोमवार मार्च की सुबह सात बजे बेगमपुर थाना पुलिस को जानकारी मिली कि जैन नगर स्थित एक मकान में आग लग गई है, जहां कुछ लोग फंसे हुए हैं। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। जहां अंदर से घर का मुख्य दरवाजा बंद मिला।

इस बीच मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने पहले आग पर काबू पाया। जिसके बाद पुलिस टीम घर के अंदर दाखिल हुई। जहां गंभीर रूप से जली हुई एक महिला बदहवास हालत में मिली। घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया।

इस बीच पुलिस को एक अन्य अस्पताल से जानकारी मिली कि महिला का पति व उनकी दो बेटियां भी इस आग से झुलस गए हैं। पुलिस टीम तुरंत अस्पताल पहुंची। जहां अस्पताल में भर्ती मृतका की बेटी ने बताया कि उनके पिता ने ही उनकी मां से झगड़ा करने के बाद केरोसिन तेल छिड़ककर आग लगा दी। पुलिस ने इस मामले हत्या की धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मकान अपने नाम कराना चाहता था आरोपी

आशीष का आरोप है कि पिछले एक महीने से वह ज्योति के साथ मारपीट कर रहा था। ज्योति ने हाल में आपनी वेतन के पैसों से जैन नगर स्थित अपने घर के पास ही जमीन खरीदकर मकान बनवाई थी। जिसमें किरायेदार को रखा हुआ था। यह दोनों मकान ज्योति के नाम पर ही था। आरोपी ज्योति पर लगातार दोनों घर अपने नाम पर करवाना चाहता था। जिसके लिए मृतका तैयार नहीं थी।

पहले केंद्रीय विद्यालय, फिर एमसीडी स्कूल में लगी थी नौकरी

मृतका के भाई कंझावला निवासी आशीष डबास ने बताया कि उनकी 39 वर्षीय बहन ज्योति की पहली नौकरी पठान कोट स्थित एक केंद्रीय विद्याल में लगी थी, साल 2005-06 में उनकी नौकरी कराला स्थित एमसीडी स्कूल में शिक्षिका के तौर पर चयनित हो गईं। ज्योति की शादी साल 2009 में झज्जर निवासी राजवीर से हुई थी। शादी से पहले ही हमने बहन को जैन नगर में एक घर गिफ्ट किया था। जहां शादी के तुरंत बार इस घर में पति के साथ रहने लगीं। राजवीर शादी के समय डीटीसी में कंडक्टर था। लेकिन समय-समय काम बदलता रहता था।

पूरा परिवार आग से झुलसा

आरोपी जैसे ही ज्योति को आग लगाने की कोशिश की, वह शोर मचाने लगी। अपने कमरे में सो रही दोनों बेटियां 12 वर्षीय अविका और डेढ़ साल की अंशु भी उठ गई। भागकर मां के पास जाने लगी, जिसमें दोनों बहनें भी झुलस गई।

गंदगी को लेकर एलजी के सवाल पर भड़के केजरीवाल, कहा- विपक्ष की भूमिका निभा रहे

उप राज्यपाल संगम विहार इलाके में लोगों के अनुरोध पर पहुंचे थे और वहां की समस्याओं को देखकर चिंता जाहिर कते हुए एक्स पर स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने नौ साल में जनता से सिर्फ मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वादे किए है लेकिन यदि संगम विहार इलाके में देखा जाए बीस लाख लोगों नरकीय जीवन जीने को मजबूर है।

दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में एलजी वी के सक्सेना द्वारा संगम विहार कालोनी में दौरे के बाद किए गए पोस्ट को लेकर एलजी और सीएम मंगलवार को आमने सामने आ गए। उपराज्यपाल सक्सेना द्वारा लोगों को बुनियादी सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित करने के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी सक्सेना विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मजबूर हैं।

एलजी की पोस्ट पर भड़के केजरीवाल

दरअसल एलजी के संगम विहार का दौरा करने के बाद की गई पोस्ट पर सीएम केजरीवाल भड़क गए। इससे पहले एलजी ने अपनी पोस्ट में कहा कि नौ साल बाद भी क्षेत्र में रहने वाले 20 लाख से अधिक लोग बदतर जीवन जीने को मजबूर हैं और कहा कि देश कल्पना नहीं कर सकता कि भारत की राजधानी में बजबजाती नालियां, कूड़े के ढेर और बदबूदार सीवर के पानी से भरी सड़कें होंगी।

उपराज्यपाल संगम विहार से पहले किराड़ी और बुराड़ी इलाकों के दौरे कर भी वहां की समस्याओं को लेकर दिल्ली सरकार की आलोचना कर चुके हैं। दरअसल एलजी वी के सक्सेना ने मंगलवार को इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर फोटो के साथ अपनी पोस्ट में कहा कि मैं स्थानीय निवासियों के अनुरोध पर सोमवार को संगम विहार गया था। नौ साल की कठिनाइयों के बावजूद क्षेत्र में रहने वाले 20 लाख से अधिक लोग ऐसा जीवन जीने को मजबूर हैं जहां वे बुनियादी सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित हैं।

एलजी ने मुख्यमंत्री से की अपील

वहां सड़कें नहीं हैं। कोई सीवर नहीं, कचरा निपटान की व्यवस्था नहीं है। अपनी पोस्ट में कुछ तस्वीरें संलग्न करते हुए सक्सेना ने कहा कि बिजली के तार बेतरतीब ढंग से लटके हुए हैं जो खतरनाक हैं, उन्होंने कहा कि उनके सामने एक रिक्शा पलट गया और एक महिला घायल हो गई। उन्होंने लिखा कि देश कल्पना नहीं कर सकता कि भारत की राजधानी में बजबजाती नालियां, कूड़े के ढेर और बदबूदार सीवर के पानी से भरी सड़कें होंगी।

सभी संबंधित विभाग पूरी तरह से दिल्ली सरकार के अधीन हैं और एमसीडी भी आपके अधीन है। एलजी ने कहा कि मुख्यमंत्री से वहां की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कहा। इससे पहले एलजी किराड़ी और बुराड़ी इलाकों का भी दौरा कर चुके हैं। एलजी की पोस्ट से नाराज केजरीवाल ने एलजी को जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव को अगले सात दिनों के भीतर उनके द्वारा बताई गई सभी क्षेत्रों की कमियों को दूर करने का आदेश दिया है।

केजरीवाल ने पोस्ट किया कि मैं मुख्य सचिव को सात दिनों के भीतर इन सभी कमियों को दूर करने का आदेश दे रहा हूं। आप जो काम कर रहे हैं वह विपक्ष को करना चाहिए था। विपक्ष का काम सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर करना है। उन्होंने लिखा कि दुर्भाग्य से, आज विपक्ष (भाजपा) के सभी सात सांसद राजनीति से संन्यास लेने में व्यस्त हैं और आठ विधायक गहरी नींद में सो रहे हैं। यही कारण है कि पिछले 26 वर्षों से दिल्ली की सत्ता भाजपा से दूर है।

केजरीवाल ने लगाया ये आरोप

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद उपराज्यपाल विपक्ष की भूमिका निभाने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी ठीक से जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो सेवा और सतर्कता विभाग एलजी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं उन्हें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए।

केजरीवाल ने कहा कि यदि यह मेरे अधीन होता तो मैं न केवल ऐसे लापरवाह अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर देता, बल्कि उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई भी करता कि कोई अन्य अधिकारी इस तरह की लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर पाता। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप इनमें से सबसे वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर देंगे ।विभाग और उन्हें अनुकरणीय सजा दे ।कहा कि दो करोड़ दिल्लीवासी आपकी कार्रवाई का इंतजार करेंगे।

नफे सिंह की हत्या के मकसद का पता लग पाना होगा मुश्किल, हरियाणा के शराब कारोबारी पर पुलिस को शक

परिवहन विशेष न्यूज

कहा जाता है कि शराब कारोबारी ने शराब के अवैध धंधे से अकूत कमाई की और अब पिछले कई वर्षों से अवैध धंधा छोड़ उसने हरियाणा में कई ठेके ले लिए। हरियाणा में वह शराब का बड़ा कारोबारी बन गया। स्पेशल सेल का कहना है कि वारदात में शामिल फरार दो शूटर नकुल सांगवान व अतुल के पकड़े जाने पर मकसद का पता लग सकता है।

नई दिल्ली। बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की हत्या में शामिल दो शूटर आशीष उर्फ बाबा व सौरभ को हरियाणा व दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गोवा से दबोच कर केस की गुत्थी सुलझा तो ली, लेकिन इनसे पूछताछ में हत्या के मकसद का पता नहीं चल पाया है। स्पेशल सेल का कहना है कि वारदात में शामिल फरार दो शूटर नकुल सांगवान व अतुल के पकड़े जाने पर मकसद का पता लग सकता है। क्योंकि नकुल, नंदू का रिश्तेदार है, हो सकता है नंदू ने उसे हत्या के मकसद के बारे में बताया हो, लेकिन इनके पकड़े जाने पर भी मकसद का पता लग पाना मुश्किल होगा। सूत्रों की मानें तो नफे सिंह राठी की हत्या के पीछे बहुत गहरी साजिश रची गई है। मामले में राजनीतिक एंगल आने के कारण पुलिस दो शूटरों के पकड़े जाने के बावजूद मकसद के बारे में कोई जानकारी देने से बच रही है। पुलिस को शक है कि हरियाणा के एक बड़े शराब कारोबारी ने नंदू को नफे सिंह राठी की हत्या की सुपारी दी है। जिस पर विदेश में बैठे नंदू ने अपने शूटरों को निर्देश देकर हत्या करवा दी। शराब कारोबारी व नंदू की दोस्ती की बहुत पुरानी कहानी है।

वर्षों पूर्व जब हरियाणा के इस शराब कारोबारी का हरियाणा से दिल्ली में अवैध शराब की आपूर्ति का धंधा चलता था तब नंदू व उसका बड़ा भाई ज्योति प्रकाश उसके धंधे को संभालता था। तिहाड़ जेल में बंद ज्योति उस दौरान उक्त शराब कारोबारी का बाउंसर होता था। बाद में कुख्यात गैंगस्टर मंजीत महाल भी उसी शराब कारोबारी के लिए काम करने लगा था।

केजरीवाल को चुनाव से पहले झटका, आप छोड़ भाजपा में शामिल हुए बलबीर सिंह जाखड़

परिवहन विशेष न्यूज

Delhi Politics 2019 में आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी रहे बलबीर सिंह जाखड़ अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष ने उनका पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री यह नहीं बता रहे हैं कि दिल्ली में पिछले पांच वर्षों में बुजुर्गों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है?

नई दिल्ली। पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से वर्ष 2019 में आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी रहे बलबीर सिंह जाखड़ अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उनका पार्टी में स्वागत किया। वकील लोकेश वर्मा, पूर्व निगम पार्षद और आप नेता राज खुराना एवं पूजा मदान भी अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सचदेवा ने कहा कि समाज के हर वर्ग और नारी शक्ति को आगे बढ़ाना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है। उनके प्रयास से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं को एक-एक हजार प्रति माह देने की घोषणा की है, लेकिन मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री यह नहीं बता रहे हैं कि दिल्ली में पिछले पांच वर्षों में बुजुर्गों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? जाखड़ ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं को सबसे आगे रखा जाता है। प्रधानमंत्री की जनकल्याणकारी नीतियां बिना किसी भेद भाव के सभी के पास पहुंच रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं।

सफदरजंग अस्पताल में अंगदान से चार लोगों को मिला नया जीवन

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। सफदरजंग अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. वंदना तलवार ने बताया कि 26 वर्षीय मृतक डोनर विजय और उनके परिवार ने उदारतापूर्वक चार मरीजों को नया जीवन दिया। परिवार हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले का रहने वाला है। वह एक सप्ताह से अस्वस्थ थे और कुछ समय से निजी उपचार पर थे। उन्हें तीव्र ज्वर की बीमारी थी और गंभीर हालत में 25 फरवरी 2024 को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 मार्च, 2024 की शाम को, कई परीक्षणों के बाद, विशेषज्ञों के एक पैनल ने उन्हें ब्रेन डेड प्रमाणित कर दिया। परिवार को अंगदान के लिए समझाया और परामर्श दिया गया, जिस पर वे अपने बेटे को खोने के भारी दुःख के बावजूद सहमत हो गए।

मृतक दाता विजय के माता-पिता इस उदारतापूर्ण कार्य के लिए सहमत हुए और प्रतीक्षा सूची वाले जरूरतमंद मरीजों के लिए अस्पताल को चार महत्वपूर्ण अंग दान करने का निर्णय लिया। अंग दान एवं प्रत्यारोपण समन्वय समिति द्वारा सफदरजंग अस्पताल में अंग पुनर्प्राप्ति सफलतापूर्वक की गई। प्राप्त अंगों को NOTTO के समन्वय से आवंटित किया गया था। मृत दाता का हृदय एम्स, नई दिल्ली में एक मरीज में प्रत्यारोपित किया गया, लीवर और एक किडनी आर एंड आर आर्मी अस्पताल में प्रत्यारोपित किया गया और एक किडनी सफदरजंग अस्पताल में नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी की संबंधित टीमों द्वारा प्रत्यारोपित की गई। सफदरजंग अस्पताल में किडनी प्राप्तकर्ता की हालत स्थिर है और वह ठीक हो रहा है। दाता के परिजनों का यह निस्वार्थ कार्य अंग दान के बारे में जनता में जागरूकता फैलाने में काफी मददगार साबित होगा।

जनवरी 2024 के महीने में सफदरजंग अस्पताल में वर्तमान मृत अंग दान और पिछला मृत अंग दान, ब्रेन स्टेम मृत्यु घोषणा और मृत अंग दान के प्रति संकाय और निवासियों में

जागरूकता बढ़ाने के लिए चल रहे कार्यक्रम के पुनरुद्धार का परिणाम है। चिकित्सा अधीक्षक ने यह भी बताया कि सफदरजंग अस्पताल में, अतिरिक्त एमएस डॉ. वंदना चक्रवर्ती और प्रभारी अधिकारी डॉ. बिनीता जयसवाल के नेतृत्व में अंग दान और प्रत्यारोपण समन्वय समिति सक्रिय रूप से जागरूकता बढ़ाने के लिए संवेदीकरण और प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर रही है संभावित ब्रेन स्टेम मृत्यु घोषणा और अंग दान।

अंग दान में एक व्यक्ति के स्वस्थ अंगों और ऊतकों को दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है। अंग केवल किसी व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु के बाद या यदि व्यक्ति को मस्तिष्क मृत घोषित कर दिया जाता है, तब ही दान किया जा सकता है, जिसे भारत में 'मानव प्रत्यारोपण' के तहत वैध किया गया था। अंग (टीएचओ) अधिनियम' 1994 में। तब से मस्तिष्क मृत दाताओं से बहु-अंग प्रत्यारोपण गतिविधि करना संभव हो गया है।

दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ SI में 4000 से ज्यादा नौकरियां, परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 29 मार्च है। आवेदन पत्र में उम्मीदवार 30 और 31 मार्च को ऑनलाइन माध्यम से सुधार कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अलावा सीएपीएफ में सब-इंस्पेक्टर के पद के लिए 4001 रिक्तियां हैं।

नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ एसआइ) परीक्षा 2024 में 4187 उप-निरीक्षक के पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर रिक्तियों के लिए 28 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 29 मार्च है। आवेदन पत्र में उम्मीदवार 30 और 31 मार्च को ऑनलाइन माध्यम से सुधार कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा।

कब होगी परीक्षा?

आरक्षण के लिए पात्र महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और पूर्व सैनिकों से संबंधित उम्मीदवारों को इससे छूट दी गई है। परीक्षा नौ, 10 और 13 मई को आयोजित की जाएगी। दिल्ली पुलिस-पुरुष में सब-इंस्पेक्टर के लिए 125 और दिल्ली पुलिस-महिला में सब-इंस्पेक्टर के लिए 61 रिक्तियां हैं। इसके अलावा, सीएपीएफ में सब-इंस्पेक्टर के पद के लिए 4001 रिक्तियां हैं।

बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से दबे चार श्रमिक, महिला की मौत; 3 अस्पताल में भर्ती

साउथ सिटी-एक में बेसमेंट की खुदाई के दौरान मंगलवार दोपहर अचानक मिट्टी ढहने से खुदाई कर रहे तीन महिला सहित चार श्रमिक दब गए। मिट्टी में दबे श्रमिकों को 20 मिनट में ही बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के तुरंत बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सभी बेहोशी की हालात में थे। अस्पताल में डॉक्टरों ने मोनिका को मृत घोषित कर दिया।

गुरुग्राम। सेक्टर 40 थाना क्षेत्र के साउथ सिटी-एक में बेसमेंट की खुदाई के दौरान मंगलवार दोपहर अचानक मिट्टी ढहने से खुदाई कर रहे तीन महिला सहित चार श्रमिक दब गए। पुलिस समेत अन्य रेस्क्यू टीमों ने 20 मिनट में ही सभी श्रमिकों को बेहोशी की हालात में बाहर निकाला। हादसे में एक श्रमिक की हुई मौत

हादसे में एक महिला श्रमिक की मौत हो गई, जबकि तीन श्रमिकों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार मोती विहार साउथ सिटी एक में स्थित खाली प्लाट में बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा था। इस काम में राजस्थान के भीलवाड़ा निवासी मोनिका, सोनिया, लाली और लाला राम काम कर रहे थे। दोपहर साढ़े तीन बजे अचानक मिट्टी ढह गई और खुदाई कर रहे चारों श्रमिक इसमें दब गए।

20 मिनट तक दबे रहे श्रमिक

आसपास के लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस, दमकल और आपदा प्रबधंन की टीम ने रेस्क्यू करते हुए मिट्टी में दबे श्रमिकों को 20 मिनट में ही बाहर निकाल लिया। सभी बेहोशी की हालात में थे। अस्पताल में डाक्टरों ने मोनिका को मृत घोषित कर दिया।

आप को मिल सकती गौतमबुद्ध नगर सीट, कैंडिडेट के लिए I.N.D.I.A से ये नाम सबसे आगे

सपा का मानना है कि गौतमबुद्ध नगर सीट दिल्ली से सटी होने का लाभ आम आदमी पार्टी प्रत्याशी को मिल सकता है। इसके लिए दोनों पार्टी के नेताओं तीन दौर की बातचीत हो चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसका असर एनसीआर में पड़ता है। ऐसे में ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की पूरी संभावना है।

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट आईएनडीआईए गठबंधन में अब आम आदमी पार्टी (आप) के खाते में जा सकती है। फिलहाल यह सीट सपा के खाते में हैं। सूत्रों की मानें तो सपा खुद चुनाव न लड़कर इस सीट को दिल्ली के नजदीक होने की वजह से आम आदमी पार्टी को दे सकती है।

AAP को मिलेगा लाभ

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसका असर एनसीआर में पड़ता है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली रोजगार के लिए जाते हैं। सपा का मानना है कि गौतमबुद्ध नगर सीट दिल्ली से सटी होने का लाभ आम आदमी पार्टी प्रत्याशी को मिल सकता है। इसके लिए दोनों पार्टी के नेताओं तीन दौर की बातचीत हो चुकी है।

पार्टी प्रत्याशी के नाम पर भी चर्चा हो चुकी है। सूत्रों की मानें तो गत विधानसभा चुनाव में नोएडा से लड़े पंकज अवाना गठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं। अगले सप्ताह इसकी घोषणा हो सकती है। शहरीकरण के कारण गौतमबुद्ध नगर को भाजपा की परंपरागत सीट माना जाता है। 1996 से 2009 तक चार बार भाजपा के अशोक प्रधान यहां से सांसद रहे।

रिकॉर्ड वोटों से जीते थे महेश शर्मा

2009 लोकसभा चुनाव में बसपा के सुरेंद्र नागर ने बाजी मारते हुए जीत हासिल की थी, लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस सीट पर फिर से कब्जा कर लिया। डॉक्टर महेश शर्मा ने पिछले चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत

हासिल की है। तीसरी बार भी वह मैदान में हैं। गत लोकसभा चुनाव में सपा-बसपा और रालोद के मजबूत गठबंधन के बावजूद भाजपा के डॉक्टर महेश शर्मा तीन लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे।

इस बार सपा-कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। बसपा अलग प्रत्याशी उतारेगी। सूत्रों की मानें तो सपा ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, बसपा छोड़ सपा में शामिल हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जयवती नागर के पति गजराज नागर व कांग्रेस छोड़ सपा में आए डॉक्टर महेंद्र नागर में से किसी एक को प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा थी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामशरण नागर ने भी दावेदारी की है।

ये नाम कैंडिडेट के रूप में सबसे आगे

बताया जाता है कि राजकुमार भाटी चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। गजराज नागर भी चुनाव लड़ने के लिए रूचि नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि, डॉक्टर महेंद्र नागर और रामशरण नागर चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी नेताओं की अनिच्छा के कारण सपा इस सीट को अब आम आदमी पार्टी के खाते में देना चाहती है। हालांकि, कांग्रेस के कुछ नेता इस सीट से चुनाव लड़ने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। इनमें वीरेंद्र गुड्डू, पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी, विदित चौधरी आदि शामिल है।

वह चाहते हैं कि यह सीट कांग्रेस के खातें में आ जाए। हालांकि, कांग्रेस की पिछले दो चुनावों में यहां काफी फजीहत हुई थी। 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रमेश चंद तोमर मतदान से तीन दिन पहले मैदान छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे। इसी तरह 2019 लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद सिंह मतदान से दो दिन पहले मैदान से गायब हो गए थे। इसलिए इस बार कांग्रेस ने इस सीट को अपने खाते में नहीं लिया। सूत्रों की मानें तो अगले तीन-चार दिन में गठबंधन प्रत्याशी की तस्वीर साफ हो जाएगी।

लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में ब्राह्मणों को साधने की कोशिश, साहिबाबाद MLA सुनील शर्मा बने मंत्री; दर्ज की थी रिकॉर्ड जीत

लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आज मंगलवार को योगी कैबिनेट विस्तार में साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा को मंत्री बनाया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 14 सीटों में से 7 सीट हार गई थी जबकि 2009 में सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा था।

गाजियाबाद। लोकसभा चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का आज मंगलवार को विस्तार किया गया है। इसमें साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा (Sunil Sharma) को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है।

इससे पहले चर्चा थी कि उनके पास राज भवन से इस संबंध में फोन कॉल आ गई है। वह साहिबाबाद से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए और वहां से उन्होंने लखनऊ के लिए फ्लाइट ली।

गाजियाबाद से उनके कई करीबी व समर्थक सड़क मार्ग से लखनऊ के लिए निकल चुके हैं। उनके काफी करीबी माने जाने वाले घनश्याम तिवारी ने बताया कि विधायक सुनील शर्मा से फोन पर बात नहीं हो पा रही है। उनके मंत्री बनाए जाने की सूचना मिली है। वह खुद भी साथियों के साथ कार से लखनऊ जा रहे हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर विशेष फोकस

उल्लेखनीय है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 14 सीटों में से 7 सीट हार गई थी जबकि 2009 में सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा था। इस वजह से इस चुनाव में भाजपा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस है।

राजनीति के जानकारों की माने तो योगी मंत्रिमंडल में सुनील शर्मा को मंत्री बनाकर भाजपा ब्राह्मणों को साधने की कोशिश करेगी। इस कदम का फायदा पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा।

दर्ज की थी रिकॉर्ड जीत

2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुनील शर्मा (Sunil Sharma) ने साहिबाबाद विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। सुनील शर्मा ने 2 लाख 14 हजार 386 वोटों से सपा गठबंधन प्रत्याशी अमरपाल शर्मा को हराया था।

इस ऐतिहासिक जीत के साथ शर्मा ने वोटों की संख्या के लिहाज से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता अजीत पवार का रिकॉर्ड तोड़ा था। बता दें कि पवार ने 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बारामती सीट पर 1 लाख 65 हजार 265 वोटों से जीत दर्ज की थी।

माउथ फ्रेशनर की जगह दी थी ड्राइ-आइस, मुंह में रखते ही होने लगी खून की उल्टियां; बिगड़ गई 5 लोगों की हालत

घटना के बाद से रेस्टारेंट बंद है। जिला फूड सेफ्टी आफिसर डॉ. रमेश चौहार ने कहा कि रेस्टोरेंट को नोटिस जारी किया गया है। इसमें पूछा गया कि आखिर किस कारण इस प्रकार की घटना हुई है। जवाब देने के बाद फूड सप्लाई विभाग यह तय करेगा कि रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द करना है या नहीं। जवाब आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

गुरुग्राम। सेक्टर 90 स्थित सफायर 90 ला फोरेस्टा रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर देने से मुंह से खून निकलने के मामले में पुलिस ने रेस्टोरेंट के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित की पहचान दिल्ली के कीर्ति नगर निवासी गगनदीप सिंह के रूप में की गई।

वहीं रेस्टोरेंट में पांच लोगों की हालत बिगड़ने पर सभी को आर्वी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां तीन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। एक की स्थित सामान्य और एक की हल्की गंभीर है। बुधवार शाम तक इन दोनों को भी डिस्चार्ज किया जा सकता है।

ग्रेटर नोएडा के ओमिरान एक निवासी अंकित शनिवार रात अपनी पत्नी नेहा, मानिक अपनी पत्नी प्रीतिका और दीपक अरोड़ा अपनी पत्नी हिमानी के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 90 स्थित सफायर 90 ला फोरेस्टा रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे।

अंकित के मुताबिक खाना खत्म होने के बाद उन्हें रेस्टोरेंट की महिला वेटर अमृतपाल कौर ने माउथ फ्रेशनर के रूप में आइस क्यूब दिया। अंकित ने अपनी एक साल की बेटी को गोद लिया हुआ था, इसलिए उन्होंने माउथ फ्रेशनर नहीं खाया, जबकि उनकी पत्नी समेत पांच साथियों ने माउथ फ्रेशनर खा लिया। इसके बाद उनके मुंह में जलन पड़ने लगी।

मुंह से खून निकलने लगा और उल्टी हुई ।तुरंत ही सभी पांचों लोगों को सेक्टर 90 स्थित आर्वी हेल्थकेयर अस्पताल ले जाया गया। इसमें से तीन लोगों की स्थिति गंभीर मिली।

स्थिति सुधरने पर किया गया डिस्चार्ज

दो की स्थिति ठीक होने पर उन्हें तुरंत ही घर भेज दिया गया। अन्य तीनों को आईसीयू में भर्ती किया गया। इसमें से एक मरीज को मंगलवार दोपहर डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी दीपक की स्थित हल्की गंभीर बनी हुई है। इन्हें 24 घंटे अतिरिक्त आईसीयू में निगरानी के लिए रखा गया है। इनका इलाज करने वाले फिजीशियन डॉक्टर स्पर्श गुप्ता ने बताया कि दीपक की स्थिति पहले काफी गंभीर थी। इनकी इंडोस्कोपी करनी पड़ी।

इसमें खाने की नली में अल्सर भी दिखाई पड़ा है। धीरे-धीरे इनकी स्थिति भी ठीक हो रही है। बुधवार शाम को इन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।अंकित ने बताया कि उनकी पत्नी की हालत फिलहाल ठीक है। अब वह घर पर हैं।

लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन?

डॉ. आशीष वशिष्ठ

भाजपा ने पिछले चुनाव में भी इस बात को खूब प्रचारित किया था कि विपक्ष के पास मोदी का कोई विकल्प नहीं है। सोशल मीडिया पर आज भी इस बात की चर्चा होती है कि आम चुनाव में विपक्ष के पास प्रधानमंत्री के लिए कौन ऐसा उम्मीदवार है, जो मोदी की बराबरी करता दिखे?

अगले कुछ दिनों में चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा।

राजनीतिक दल चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। देश का राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपानीत एनडीए का चेहरा नरेंद्र मोदी हैं। ऐसे में अहम प्रश्न है कि मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा? क्या विपक्ष चुनाव मैदान में उतरने से पहले किसी एक चेहरे पर सहमति बना पाएगा? या फिर विपक्ष बिना चेहरे के ही मोदी को चुनौती देगा? विपक्ष अभी तक यह तय नहीं कर पाया है कि मोदी के सामने कौन विपक्ष को चेहरा कौन होगा।

भाजपा ने पिछले चुनाव में भी इस बात को खूब प्रचारित किया था कि विपक्ष के पास मोदी का कोई विकल्प नहीं है। सोशल मीडिया पर आज भी इस बात की चर्चा होती है कि आम चुनाव में विपक्ष के पास प्रधानमंत्री के लिए कौन ऐसा उम्मीदवार है, जो मोदी की बराबरी करता दिखे? इसका कोई जवाब विपक्ष के पास नहीं है। विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अनेक हैं। दलों में क्षेत्रीय स्तर पर टकराव बहुत हैं। इनके चलते विपक्ष चुनाव, संसद के भीतर या सड़क पर सरकार के खिलाफ एकजुट नहीं दिखाई देता है। नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता का प्रयास किया था, लेकिन कांग्रेस के रवैये से रुष्ट होकर वो दोबारा एनडीए में शामिल हो चुके हैं।

इंडी अलायंस पिछले दस महीने में आधा दर्जन बैठकों के बाद भी किसी एक चेहरे के नाम पर सहमति नहीं बना पाया। विपक्ष का हर नेता स्वयं को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार समझता है। 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई बीजेपी सामने आई तब से देश में चेहरा आधारित चुनाव का नया दौर शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी के सामने विकल्प कौन? यह विपक्ष का सबसे अनसुलझा सवाल रहा। बीता साल भी विपक्ष ने इसी के जवाब में निकाल दिया। विपक्ष ने 27 दलों का इंडी अलायंस भी बनाया तब भी उसमें एक आम चेहरा सामने नहीं ला पाया।

वहीं अगर पिछले कुछ सालों का रिकार्ड देखें तो जिस राज्य में विपक्ष ने विधानसभा चुनाव में मजबूत चेहरा रखा वहां उसे विजय हासिल हुई। लेकिन केंद्र में आकर वह ऐसा करने में विफल रहा। बीती 19 दिसंबर को इंडी अलायंस की मीटिंग में यह मसला उठा और कुछ नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का नाम आगे किया लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोर देकर कहा कि विपक्षी दलों के लिए पहली प्राथमिकता आम चुनाव जीतना और फिर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम तय करना होगा। उन्होंने कहा, ''आवश्यक सदस्यों के बिना पीएम उम्मीदवार के बारे में चर्चा निरर्थक है।'' खड़गे के गैर-प्रतिबद्ध रुख ने संकेत दिया कि गठबंधन का चेहरा नामित करने का मुद्दा विवादास्पद बना हुआ है। जबकि तमाम आंकड़े और सर्वेक्षण बताते हैं कि आजकल मतदाता चुनाव में नेतृत्व की स्पष्टता वाले दल की ओर अधिक जाना पसंद करते हैं।

ऐसे में विपक्ष के लिए इस अनसुलझे प्रश्न की तलाश सबसे अधिक है। मुकाबला तो साफ तौर पर घोषित उम्मीदवारों के बीच होता है। जब विपक्ष ने किसी को अपना चेहरा घोषित ही नहीं कर पाया, ऐसे में आमजन में यह संदेश गया कि विपक्ष के पास मोदी का मुकाबला करने वाला कोई नाम और चेहरा नहीं है। बिना किसी चेहरे के विपक्ष अपनी आधी लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार चुका है।

इंडी अलायंस के गठन के पहले ही दिन से कांग्रेस बड़ी चालाकी से गठबंधन के संयोजक के मुद्दे पर हीलाहवाली करती रही। सीट बंटवारे को लेकर भी उसका रूख कभी साफ नहीं रहा। वास्तव में कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से नीतीश कुमार के बनाए मंच पर अपना वर्चस्व और प्रभुत्व स्थापित कर लिया। और रणनीति के तहत वो संयोजक के नाम की घोषणा जैसे अहम मुद्दे को बैठक दर बैठक टालती रही। गठबंधन में संयोजक ही प्रधानमंत्री पद का चेहरा होता। कांग्रेस यह नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा चेहरा गठबंधन की ओर से घोषित किया जाए। हालांकि कांग्रेस की चालाकी को नीतीश, केजरीवाल और ममता भांप गए। इसलिए इन तीन नेताओं ने कांग्रेस के रवैये की आलोचना करने से परहेज नहीं किया।

नीतीश तो गठबंधन से अलग हो गए। ममता ने मल्लिकार्जुन का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाकर राहुल और अन्य संभावित प्रत्याशियों का रास्ता रोकने का काम किया। केजरीवाल कांग्रेस के साथ आए भी तो अपनी शर्तों पर। कांग्रेस ने झुककर आप से सीटों का बंटवारा किया। ममता अकेले चुनाव लड़ने का संदेश दे ही चुकी है। मतलब साफ है कि गठबंधन में कोई किसी को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहता। विपक्ष का हर नेता स्वयं को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानता है। और वो प्रधानमंत्री पद के लिए अपना रास्ता साफ रखना चाहता है।

देष की जनता विपक्षी नेताओं के चाल चरित्र और सत्ता की लोलुपता को बड़े ढंग से देख रही है। जनता को पता है कि एक ओर प्रधानमंत्री मोदी जैसे ऊर्जावान और निस्वार्थ व्यक्ति है, जो अहर्निशं देश

> “ नीतीश तो गठबंधन से अलग हो गए। ममता ने मल्लिकार्जुन का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाकर राहुल और अन्य संभावित प्रत्याशियों का रास्ता रोकने का काम किया। केजरीवाल कांग्रेस के साथ आए भी तो अपनी शर्तों पर। कांग्रेस ने झुककर आप से सीटों का बंटवारा किया। ममता अकेले चुनाव लड़ने का संदेश दे ही चुकी है। मतलब साफ है कि गठबंधन में कोई किसी को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहता। विपक्ष का हर नेता स्वयं को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानता है।

और देशवासियों के कल्याण और विकास के बारे में सोचता है। और दूसरी ओर एक ऐसा गठबंधन है, जिसके अधिकांश नेता अपना वर्तमान और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं। उन्हें मोदी को अपने सत्ता सुख के लिए हराना है।

विपक्ष देश की जनता को कभी यह नहीं बताता कि वो मोदी को हटाकर उनके लिए क्या करेंगे? देश के विकास का उनका मॉडल क्या है? उन्होंने देश के प्रगति का कौन सा रोडमैप तैयार किया है? विपक्ष मुफ्त की सौगातों और न पूरे होने वाले वायदे देकर सत्ता हासिल करने की कोशिशों में जुटा है। मोदी सरकार के हर काम की आलोचना और अड़चन को ही विपक्ष अपना धर्म और कर्तव्य मानता है। उसके पास कोई देश को आगे बढ़ाने का कोई माडल, रोडमैप और ब्लूप्रिंट नहीं है। देशवासी सब कुछ देख रहे हैं। पिछले दस वर्षों में देश में जो परिवर्तन और विकास हुआ है, उसे विपक्ष के नेता अपने बयानों की चादर से ढक नहीं सकते। सरकारी योजनाओं से करोड़ो देशवासी लाभन्वित हुए हैं। सरकारी कार्यप्रणाली में निष्पक्षता और पारदर्शिता का प्रतिशत बढ़ा है।

प्रधानमंत्री मोदी पिछले दो महीने में कई अवसरों पर अपने तीसरे कार्यकाल का जिक्र कर चुके हैं। बीती 3 मार्च को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। मौजूदा सरकार की यह आखिरी कैबिनेट बैठक थी। करीब 11 घंटे चली मीटिंग में विजन डॉक्यूमेंट विकसित भारत 2047, अगले 5 साल की योजनाओं और सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान पहले 100 दिन की रणनीति पर चर्चा हुई। जहां एक ओर विपक्ष के कई बड़े नेता अपने लिए सुरक्षित सीटें और गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर उलझे हुए हैं। वहीं पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल की रणनीति तय कर रहे हैं। पीएम मोदी के आत्मविश्वास से अंदर ही अंदर समूचे विपक्ष में घबराहट है।

पिछले वर्ष पांच राज्यों के चुनाव में मोदी की गारंटी विपक्ष के वायदों पर भारी पड़ी थी। देशवासियों ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। इंडी अलायंस भी मोदी को हराने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा। कांग्रेस तो अपना स्तर गिराकर समझौते और गठबंधन करने से भी परहेज नहीं कर रही है। लेकिन अहम सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के छवि, कद और नेतृत्व के सामने क्या विपक्ष की बिना चेहरे वाली रणनीति कामयाब हो पाएगी?

इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी के चेहरे के सामने में विपक्ष की बिना चेहरे वाली एकजुटता जरूरी कमजोर नजर आएगी। लेकिन, इससे उसके असफल होने की गारंटी नहीं है। यदि विपक्ष सत्ता विरोधी लहर को भुनाने में कामयाब होता है और सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले जाने में सफल रहता है तो फिर उसे फायदा होगा। लेकिन, यदि सत्ता विरोधी लहर नजर नहीं आती है तो फिर मोदी के चेहरे का फायदा फिर भाजपा को मिलेगा।

BYD Seal की एंट्री के साथ कंपनी ने बनाया जबरदस्त प्लान, 2024 के अंत तक 90 प्रतिशत ईवी मार्केट पर कब्जे की तैयारी

BYD India ने आज यानी 5 मार्च को 41 लाख रुपये से 53 लाख रुपये के बीच अपनी इलेक्ट्रिक सेडान BYD Seal लॉन्च की है। इसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी Atto 3 के लिए ARAI से होमोलोगेशन सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए काम कर रही है जो 2500 यूनिट की आयात मात्रा पर प्रतिबंध हटा देगी। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता BYD ने साल के अंत तक भारत में 90 प्रतिशत ईवी बाजार को कवर करने की योजना बनाई है, क्योंकि ये 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले ईवी में नेतृत्व की स्थिति को मजबूत करता है। ये जानकारी कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी।

कंपनी की ये है तैयारी

BYD India ने आज यानी 5 मार्च को 41 लाख रुपये से 53 लाख रुपये के बीच अपनी इलेक्ट्रिक सेडान BYD Seal लॉन्च की है। इसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी Atto 3 के लिए ARAI से होमोलोगेशन सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए काम कर रही है, जो 2500 यूनिट की आयात मात्रा पर प्रतिबंध हटा देगी। आपको बता दें कि होमोलोगेशन देश में निर्मित या आयातित सभी वाहनों के लिए सरकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों के तहत सड़क योग्यता के लिए वाहनों को प्रमाणित करने की प्रक्रिया है।

BYD India 90 प्रतिशत ईवी मार्केट कवर करेगी

बीवाईडी इंडिया के इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन व्यवसाय के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय गोपालकृष्णन ने लॉन्च के मौके पर कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हम भारत में 90 प्रतिशत ईवी बाजार को कवर करें। हम इस साल तक यही करने की योजना बना रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम प्रमुख शहरों और टियर I शहरों में मौजूद होंगे।

BYD के अभी कितने शोरूम?

वर्तमान में BYD India के पैसेंजर वाहन सेगमेंट के पास 21 शहरों में 24 शोरूम के साथ एक डीलरशिप नेटवर्क है, जो अपने पोर्टफोलियो में दो उत्पाद BYD ATTO 3 और e6 बेच रही है। भारत में पैसेंजर ईवी वर्तमान में ज्यादातर महानगरों और टियर I शहरों में बेची जाती हैं और धीरे-धीरे कम कीमत वाले मॉडलों में टियर II को भी कवर कर रही हैं।

मशहूर F1 ड्राइवर की फरारी 29 साल पहले ऑस्ट्रेलिया से हुई थी चोरी, अब ब्रिटेन में पुलिस ने ऐसे की बरामद

लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि उन्होंने फेरारी से एक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद जनवरी में एक जांच शुरू की थी जिसमें 2023 में यूके ब्रोकर के माध्यम से एक अमेरिकी खरीदार द्वारा खरीदी गई कार की जांच की गई थी जिसमें पता चला कि यह चोरी हो गई थी। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। मशहूर F1 Driver Gerhard Berger की 1995 में चोरी हुई रेड फेरारी को ब्रिटेन की Metropolitan Police ने 2024 में बरामद किया है। चोरी होने के 29 साल बाद मिलने वाली इस कार की बड़ी रोचक कहानी है। आइए, पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

29 साल पहले हुई थी चोरी

Gerhard Berger और उनके साथी Jean Alesi ने अप्रैल 1995 में एक ही दिन इमोला में सर्किट के पास काम कर रहे कार चोरों के हाथों अपनी निजी कारें खो दीं। ऑस्ट्रियाई F1 Driver ने बताया कि उनकी रेड F512M Testarossa उनके होटल के बाहर से गायब हो गई थी।

कैसे वापस मिली कार?

लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि उन्होंने फेरारी से एक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद जनवरी में एक जांच शुरू की थी, जिसमें 2023 में यूके ब्रोकर के माध्यम से एक अमेरिकी खरीदार द्वारा खरीदी गई कार की जांच की गई थी, जिसमें पता चला कि यह चोरी हो गई थी।

4 दिन में बदला खेल!

अधिकारियों ने चार दिनों के अंदर कार की पृष्ठभूमि का पता लगाया, जिससे पता चला कि इसे बर्जर से चोरी होने के तुरंत बाद जापान भेज दिया गया था और फिर 2023 के अंत में यूके लाया गया था। इसके बाद पुलिस ने ब्रिटेन से एक्सपोर्ट रोकने के लिए वाहन को अपने कब्जे में ले लिया।

इस इन्वेस्टिगेशन को लीड करने वाले अधिकारी माइक पिलबीम ने कहा कि चोरी हुई फेरारी, जिसकी कीमत £ 350,000 के करीब है और ये 28 साल से अधिक समय से गायब थी और हम इसे केवल चार दिनों में ट्रैक करने में कामयाब रहे हैं।

Gerhard Berger कौन हैं?

बर्जर अपने 14 सीजन के फॉर्मूला वन करियर के दौरान सबसे लोकप्रिय ड्राइवरों में से एक थे, जो 1984 में शुरू हुआ और 1997 में समाप्त हुआ। उन्होंने 10 ग्रैंड प्रिक्स जीते और दो बार फेरारी के लिए ड्राइविंग करते हुए चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल किया है।

कीमत और स्पेसिफिकेशन के मामले में कौन बेहतर? किसे खरीदा तो पछताओगे

नई बजाज पल्सर NS200 में 199.5 सीसी सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन है। 6-स्पीड ट्रांसमिशन से युक्त E20-अनुरूप इंजन 9750 आरपीएम पर 24.13 बीएचपी की अधिकतम शक्ति और 8000 आरपीएम पर 18.74 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है। वहीं हीरो एक्सट्रीम 200एस 4वी में 199.6 सीसी सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो 8500 आरपीएम पर 18.8 बीएचपी की अधिकतम पावर और 6500 आरपीएम पर 17.35 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है।

नई दिल्ली। बजाज ऑटोने कुछ दिन पहले ही भारत में Pulsar NS200 का अपडेटेड वर्जन 157,427 रुपये एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। अपडेटेड NS200 के इस लॉन्च के साथ घरेलू दोपहिया निर्माता का लक्ष्य तेजी से बढ़ते 200 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी बिक्री को बढ़ावा देना है।

बजाज की इस मोटरसाइकिल का मुकाबला TVS Apache RTR 200 4V और Hero Xtreme 200S 4V से होगा। आइए, Pulsar NS200 और Xtreme 200S 4V के बारे में जान लेते हैं।

स्पेसिफिकेशन

नई बजाज पल्सर NS200 में 199.5 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन है। 6-स्पीड ट्रांसमिशन से युक्त, E20-अनुरूप इंजन 9,750 आरपीएम पर 24.13 बीएचपी की अधिकतम शक्ति और 8,000 आरपीएम पर 18.74 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है।

दूसरी ओर, हीरो एक्सट्रीम 200एस 4वी में 199.6 सीसी सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 8500 आरपीएम पर 18.8 बीएचपी की अधिकतम पावर और 6500 आरपीएम पर 17.35 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है। इंजन को 5-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है।

बजाज पल्सर NS200 हीरो मोटोकॉर्प के अपने प्रतिद्वंद्वी Xtreme 200S 4V की तुलना में अधिक शक्ति और थोड़ा अधिक टॉर्क प्रदान करती है।

कीमत

नए लॉन्च किए गए अपडेटेड बजाज पल्सर NS200 की कीमत 1.57 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। दूसरी ओर, हीरो एक्सट्रीम 200S 4V की कीमत 1.41 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। हीरो एक्सट्रीम 200S 4V की तुलना में बजाज पल्सर NS200 की कीमत थोड़ी अधिक है।

आरई शॉटगन 650 वर्सेज सुपर मीटेऑर 650

इंजन है एक लेकिन अंतर अनेक, खरीदने से पहले जान लो नहीं तो पछताओगे

RE Shotgun 650 vs Super Meteor 650 की बात करें तो दोनों मोटरसाइकिलों की चेसिस दिखने में एक जैसी ही है लेकिन उनके लुक में कुछ बड़े अंतर हैं। सुपर मीटिओर 650 की राइडिंग क्वालिटी थोड़ी मजबूत है जिसके कारण ये कुछ लोगों के लिए थोड़ा असुविधाजनक हो सकती है। यहीं पर शॉटगन 650 थोड़ा क्षमाशील है क्योंकि इसके सस्पेंशन काफी कम्फर्टेबल हैं।

नई दिल्ली। Royal Enfield Shotgun 650 को पेश करने के साथ कंपनी ने अपनी 650 सीसी पोर्टफोलियो को 4 मोटरसाइकिलों तक एक्सटेंड किया है। नई मोटरसाइकिल Super Meteor 650 से नीचे है, लेकिन इसके साथ काफी कुछ साझा करती है। आइए, इन दोनों के बारे में जान लेते हैं।

डिजाइन

दोनों मोटरसाइकिलों की चेसिस दिखने में एक जैसी ही है, लेकिन उनके लुक में कुछ बड़े अंतर हैं। सुपर मीटियोर 650 एक फुली डेवलप क्रूजर है, जिसमें एक हैंडलबार है, जो राइडर की ओर आता है और एक स्कूप-आउट सीट, एक बड़ा लार्ज टियर ड्रॉप शेप्ड फ्यूल टैंक मिलता है।

इसके बाद शॉटगन 650 है, जिसमें चौड़े हैंडलबार और मिड-सेट फुट पेग्स के साथ स्पोर्टीनेस का संकेत दिया गया है। इसके अलावा, शॉटगन 650 की पिछली सीट को हटाया जा सकता है, ताकि इसे बॉबर में अपडेट किया जा सके।

इंजन

दोनों मोटरसाइकिलों में एक ही इंजन का उपयोग किया गया है। यह 648 सीसी, पैरेलल-ट्विन इंजन है, जिसमें 270-डिग्री क्रैंक मिलता है और यह एयर-ऑयल कूल्ड है। ये लगभग 46 बीएचपी की अधिकतम पावर और 52 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है।

ये इंजन अपने टॉर्की नेचर, अच्छे एग्जॉस्ट नोट और बेहतरीन परफॉरमेंस के लिए जाना जाता है। गियर की बात करें तो, ऑन ड्यूटी गियरबॉक्स एक 6-स्पीड यूनिट है, जो गियर में सटीक रूप से फिट हो जाता है।

राइडिंग क्वालिटी

सुपर मीटिओर 650 की राइडिंग क्वालिटी थोड़ी मजबूत है, जिसके कारण ये कुछ लोगों के लिए थोड़ा असुविधाजनक हो सकती है। यहीं पर शॉटगन 650 थोड़ा क्षमाशील है, क्योंकि इसके सस्पेंशन काफी कम्फर्टेबल हैं।

अधिक अवशोषित करने की क्षमता है। इसलिए, यदि आप आराम की तलाश में हैं तो निश्चित रूप से शॉटगन एक बेहतर विकल्प होगा।

कौन ज्यादा बेहतर?

यदि आप एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहते हैं, जिसका उपयोग ज्यादातर अर्बन ड्यूटी के लिए किया जाएगा, तो शॉटगन 650 अधिक उपयुक्त है। इसके अलावा, अगर राइडर विंडस्क्रीन का विकल्प चुनता है, तो यह हाईवे ड्यूटी भी आसानी से कर सकती है।

कीमत

सुपर मीटियर 650 की कीमत ₹3.64 लाख से ₹3.94 लाख के बीच है, जबकि शॉटगन 650 की कीमत ₹3.59 लाख से शुरू होती है और ₹3.73 लाख तक जाती है। आपको बता कें कि ये सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं।

एमएसपी को कानूनी दर्जे से मजबूत होगी कृषि

अरविंद सरदाना

कृषि के मामले में स्पष्ट है कि सरकार 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करती है, जबकि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से कुछ ही इलाकों में मुख्यतः गेहूं और धान भर खरीदती है। यानी एमएसपी पर उपज खरीदने की सरकारी घोषणा महज कागजी होती है। सरकार की दलील रही है कि यदि वह सभी फसलें खरीदे तो उसका वित्तीय बोझ असहनीय हो जाएगा।

किसानों को उचित भाव मिलना और खेती में सुरक्षा एवं गरिमा महसूस करना महत्वपूर्ण लक्ष्य है। खेती को मिश्रित फसल चक्र पर ले जाना कृषि विकास के लिए जरूरी कदम होगा। मंडी व्यवस्था को बेहतर-न्यायसंगत बनाना कृषि बाजार के लिए उचित होगा। एमएसपी को कानूनी स्वरूप देना कृषि विकास के लिए एक मौका है'

कृषि के मामले में स्पष्ट है कि सरकार 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करती है, जबकि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से कुछ ही इलाकों में मुख्यतः गेहूं और धान भर खरीदती है। यानी एमएसपी पर उपज खरीदने की सरकारी घोषणा महज कागजी होती है। सरकार की दलील रही है कि यदि वह सभी फसलें खरीदे तो उसका वित्तीय बोझ असहनीय हो जाएगा। ऐसे में इस दलील को परखना जरूरी है। मूल बात यह है कि सरकारी खरीदी एवं निजी बाजार-व्यापार साथ-साथ चलते हैं। ये व्यवस्थाएं कॉम्पिटिशन के साथ एक दूसरे की पूरक बन जाती हैं। इन 23 एमएसपी फसलों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। अव्वल तो कुछ फसलें ऐसी हैं जिनका निजी बाजार मजबूत है, खासकर जिनकी कारखानों के लिए खरीदी होती है। इन फसलों के लिए एमएसपी एक न्यूनतम भाव, यानी मंडी में फ्लोर प्राइस बन सकती है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं- वर्ष 2023 में फसल आने पर सोयाबीन का भाव 4500 रुपए से 5000 रुपए क्विंटल था। व्यापारी मिलों के लिए सोयाबीन मण्डियों से खरीद रहे थे। एमएसपी का भाव 4600 रुपए क्विंटल था। एक वर्ष पहले यह भाव 6000 रुपए क्विंटल के ऊपर था। यदि विशेष परिस्थितियों में मण्डियों में बोली लगातार एमएसपी के नीचे लग रही हो तो सरकार को दखल देना चाहिए।

यह दो तरीकों से हो सकता है। मण्डियों के कर्मचारी यह व्यवस्था सुनिश्चित करें कि किसान के माल की बोली एक निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार एमएसपी से कम दाम पर न हो। जहां मिल द्वारा उपज खरीदी जाती है, वह भी एमएसपी से कम पर न हो। यदि भाव को नियंत्रित करना जरूरी हो तो अंशकालिक सरकारी खरीदी खोल देनी चाहिए। कॉम्पिटिशन से निजी बाजार पर प्रभाव पड़ेगा और दाम ऊपर आएंगे। कई व्यापारिक फसलें जिनका आमतौर पर बाजार भाव एमएसपी के ऊपर रहता है, उनके लिए सरकार को उपार्जन की जरूरत नहीं है। कभी-कभी सरकारी खरीदी करना पड़ सकती है। दूसरी सूची उन फसलों की होगी जिनका कटाई के बाद का भाव एमएसपी से 10 से 30 प्रतिशत नीचे रह सकता है। उदाहरण के लिए जब मक्का का भाव कटाई के समय 1750 रुपए क्विंटल था तब एमएसपी का भाव 2090 रुपए क्विंटल था। इस दौरान किसी को भी एमएसपी नहीं मिल रही थी। इस फसल पर निजी बाजार एमएसपी के नीचे ही चलता रहा। ऐसी स्थिति में सरकार के लिए केवल एमएसपी के नियम को लागू करने से काम नहीं चलेगा। भाव को ऊपर खींचना होगा। इसके लिए सरकार को विकेंद्रीकृत तरीके से हर जिले में छोटे-छोटे उपार्जन-केंद्र खोलने होंगे और 10 से 40 प्रतिशत फसल खरीदने की व्यवस्था बनानी होगी। उदाहरण के लिए गेहूं को देखें। एक जिले में 50 से अधिक उपार्जन केंद्र हैं। किसान पंजीयन करते हैं और उन्हें पास का केंद्र मिल जाता है। उपार्जन के बाद पैसे उनके बैंक खाते में डाल दिए जाते हैं। इस विकेंद्रीकृत व्यवस्था के कारण 30 से 50 प्रतिशत किसान इसका लाभ ले पाए। बड़ी बात यह रही कि निजी व्यापार पर कॉम्पिटिशन का असर पड़ा और मंडी के भाव एमएसपी के पास या अधिक रहे। उपार्जन ने निजी व्यापार भाव को भी ऊपर उठाया। 40 से 60 प्रतिशत व्यापार निजी बाजार से हुआ और किसानों को उचित भाव मिले।

नया कानून इसको सुनिश्चित कर सकता है। हर वर्ष एमएसपी की घोषणा के साथ-साथ विकेंद्रीकृत उपार्जन व्यवस्था की घोषणा अनिवार्य होनी चाहिए। हर राज्य के लिए कुछ ऐसी फसलों को (गेहूं और चावल को छोडक़र) चुना जाए जिनका निजी व्यापार या मंडी भाव ऊपर उठाया जा सकता है। यह सार्वजनिक हित में होगा और किसान के लिए प्रोत्साहन बनेगा तथा मिश्रित खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। हर राज्य की सूची अलग होगी, पर सभी को मिलाकर देखें तो 23 एमएसपी फसलों में अधिकांश को कवर कर पाएंगे। इसे अनिवार्य करने के लिए एमएसपी की घोषणा से उपार्जन को जोडऩा होगा और केंद्र द्वारा संचालित एफसीआई को जिम्मेदारी एवं वित्तीय खर्च उठाना होगा। हर राज्य के लिए गेहूं और धान के साथ चुनिन्दा क्षेत्रीय फसलों पर यह नियम लागू होगा। केन्द्र और राज्य इसे तय करेंगे। कई मायनों में एफसीआई का काम बढ़ेगा। उन्हें उन राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर या सार्वजनिक व्यवस्था में निवेश करना होगा जहां आज उपार्जन की व्यवस्था नहीं है। एफसीआई को गेहूं और चावल इन नए इलाकों से भी खरीदने होंगे और उसे अन्य फसलों के लिए भंडारण और वितरण की व्यवस्था बनानी होगी। गेहूं और चावल को छोडक़र एफसीआई को 30 प्रतिशत दूसरी फसलों का भण्डारण करना चाहिए, अन्यथा बिना उपार्जन वाली एमएसपी व्यवस्था एक खोखली घोषणा भर बनी रहेगी। जैसा पहले कहा गया है, केवल उपार्जन से बात नहीं बनेगी। मंडी में निजी बाजार भाव को ऊपर उठाना होगा। 60-70 प्रतिशत व्यापार निजी बाजार से होना है। इसके लिए राज्य सरकार को सार्वजनिक मंडी को मजबूत बनाना होगा और उसमें निवेश करना होगा। पारंपरिक मंडी को बेहतर बनाना और वहां खुली नीलामी एवं निगरानी की व्यवस्था कायम करनी होगी।

इन सब पर अध्ययन हैं, लेकिन उनकी अनुशंसाओं पर काम नहीं हुआ है। तीसरी सूची उन फसलों की है जिनका बाजार भाव एमएसपी से बहुत दूर है। कई दशकों की मार से इन फसलों की मांग घट गई है। किसानों ने इन्हें लगभग छोड़ दिया है। इनमें मोटा अनाज शामिल है जो सबसे पौष्टिक है, पर इनका चलन बहुत कम है। उदाहरण के लिए ज्वार एक समय मुख्य अनाज होता था। दो वर्ष पहले उसका मण्डी भाव 1300 रुपए क्विंटल से 1450 रुपए क्विंटल था, जबकि एमएसपी 2738 रुपए क्विंटल था। ऐसी परिस्थिति में केवल सरकारी खरीदी से बात नहीं बनेगी। यहां लक्ष्य होगा कि जनमानस में फिर से इसका चलन बने। ज्वार, बाजरा, जौ, रागी आदि इसी समूह में आते हैं। इनकी खपत बढ़ाना जरूरी लक्ष्य होना चाहिए, तभी किसान इनकी खेती के लिए प्रोत्साहित होंगे। यहां सरकारी खरीदी के साथ-साथ उत्पादन के लिए विशेष मदद करनी होगी। इन समूहों को देखते हुए यह बात साफ हो जाती है कि हर राज्य को अपनी परिस्थितियों के अनुसार लक्ष्य बनाना होगा। एमएसपी का मॉडल केंद्रीय कानून हो सकता है, जिसे राज्यों को अपनाते हुए नियम एवं योजनाओं को बनाना होगा।

यहां किसान संगठनों की अहम भूमिका होनी चाहिए क्योंकि मिश्रित खेती पर लौटने के लिए किसानों से चर्चा करके योजना बनाई जानी चाहिए। केंद्रीय कानून में राज्यों को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान होना चाहिए, ताकि वे व्यवस्था बना पाएं। अन्यथा हम कभी गेहूं-धान के चक्र से नहीं निकल सकते। अक्सर एमएसपी के संदर्भ में कहा जाता है कि वित्तीय बोझ होगा। यदि हम मानकर चलें कि फसलों के लिए हमें सरकारी उपार्जन और निजी बाजार दोनों की जरूरत है, तो उपार्जन का खर्चा अपने आप कम हो जाता है। दूसरा, इसे सब्सिडी की नजर से न देखकर निवेश के रूप में देखें। क्या इस निवेश से विकास की पूर्ति हो रही है? किसानों को उचित भाव मिलना और खेती में सुरक्षा एवं गरिमा महसूस करना महत्वपूर्ण लक्ष्य है। खेती को मिश्रित फसल चक्र पर ले जाना कृषि विकास के लिए जरूरी कदम होगा। मंडी व्यवस्था को बेहतर और न्यायसंगत बनाना कृषि बाजार के लिए उचित होगा। खाद्य नीति को केवल गेहूं-धान तक सीमित नहीं रखकर उसमें मोटे अनाज, तेल और दालों को शामिल करना जरूरी है। एमएसपी को कानूनी स्वरूप देना मजबूरी नहीं, कृषि विकास के लिए एक मौका है।

संपादक की कलम से

हिमाचल में रेल के सपने

अंब-अंदौरा के बाद एक और वंदे भारत ट्रेन हिमाचल के नजदीक पहुंच रही है। दरअसल वैष्णो देवी दौड़ रही वंदे भारत अब पठानकोट कैंट में रुकेगी, तो पंख फैलाए हिमाचल को दूर से ही सही इसमें बैठने का मौका मिल जाएगा। हम इसमें भी खुश हैं कि पठानकोट से ही देश के साथ कदमताल का अवसर मिल गया, वरना सपनों की ट्रेन तो आज भी कम चौड़ी पटरियों पर जगह तलाश रही है। वंदे भारत का पठानकोट में रुकना हिमाचल को कितना समृद्ध कर रहा है, इसको लेकर शाबाशियों और आत्म श£ाघा का एक दौर जरूर चलेगा, लेकिन हिमाचल की असली ट्रेन है कहां। अब अंब-अंदौरा की वंदेभारत ज्यादा व्यावहारिक होगी या पठानकोट कैंट की, इस पर यात्रीगण जरूर ध्यान देंगे, लेकिन राहत यह कि दिल्ली का सफर सीधा होने जा रहा है। पर्यटन और ट्रेन के बीच घनिष्ठता उन संभावनाओं को ढोती है, जो भविष्य की आर्थिकी का समाधान है। विडंबना यह है कि हिमाचल के आसपास जम्मू-कश्मीर की पटरियां बिछती गईं और हम अंग्रजों की विरासत में नैरो गेज ट्रेन के शहतीर बनकर धंसते गए। कम से कम कांगड़ा की तरफ तो रेलवे विस्तार की दिशा में सिर्फ यही खबर आई कि ब्रिटिश पीरियड में निर्मित बैजनाथ-पपरोला रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा, वरना वही पटरियां और वही गति। बारिश की आपदा ने रोकी, तो महीनों रुक गई कांगड़ा घाटी की रेलगाड़ी। यह दीगर है कि बिलासपुर की ट्रेन करवट ले रही है और ऊना की पटरियां फैल रही हैं, लेकिन रेलवे का इतिहास कांगड़ा-मंडी और चंबा में शर्मिंदा है। ऐसे में वंदे भारत के नखरे में सवार होना भी गनीमत है, भले ही पठानकोट या अंब-अंदौरा पहुंचते-पहुंचते खासी मेहनत करनी पड़े।

बेशक वंदे भारत के दो विकल्प पर्यटन के रास्तों को सरल कर देंगे और अगर इनके साथ एचआरटीसी के रूट समाहित कर दें, तो दिल्ली से अंब-अंदौरा या अब पठानकोट से आगे डेस्टिनेशन टूरिज्म तक पहुंचना सुविधाजनक होगा। बावजूद इसके हिमाचल के हिस्से में भी कुछ पटरियां चाहिएं। पठानकोट से जोगिंद्रनगर की एक सदी पुरानी ट्रेन भले ही धरोहर बन जाए, लेकिन इसके आसपास कुछ तो निगाह चाहिए। हमारा मानना है और यही एक मात्र विकल्प साबित होगा कि अंब-अंदौरा तक पहुंची रेल लाइन का एक रुख ज्वालाजी मंदिर की ओर मोड़ दिया जाए। ज्वालाजी मंदिर तक ट्रेन का आना धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से, क्रांतिकारी प्रयास होगा, क्योंकि इसके कारण चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, दियोटसिद्ध, कांगड़ा, चामुंडा व बैजनाथ तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। ज्वालाजी मंदिर तक रेलवे मार्ग बिछे तो इसे आसानी से कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, चंबा और बिलासपुर की ओर बढ़ाया जा सकता है। आश्चर्य यह कि हिमाचल की प्राथमिकताएं कागजी नक्शों पर सियासत की अपनी-अपनी गोटियां फिट करके भविष्य की रूपरेखा को सुदृढ़ नहीं कर पातीं।

यह तय है कि पठानकोट से अब मंडी की ओर नई ब्रॉडगेज लाइन नहीं बिछेगी। यह इसलिए भी कि भानुपल्ली-बिलासपुर रेल मार्ग ही इस दृष्टि से आगे मंजिल देखेगा। ऐसे में अंब-अंदौरा से ज्वालाजी मंदिर रेल मार्ग को धार्मिक पर्यटन से जोडक़र देखना होगा। रेलवे के साथ फिफ्टी-फिफ्टी पार्टनरशिप पर मंदिर रेल परियोजना बनाकर हिमाचल कोंकण रेलवे की तरह आगे बढ़ सकता है। बहरहाल वंदे भारत ट्रेन का अंब अंदौरा तक आगमन हमीरपुर, ऊना व कांगड़ा के लिए सुखद अनुभव रहा है। ऐसे में वाया पठानकोट वंदे भारत ट्रेन के साथ हिमाचल का जुडऩा वरदान साबित होगा। इन दोनों ट्रेनों की क्षमता में हिमाचल की जनता को सुविधाजनक तरीके से जोडऩे के लिए एचआरटीसी को ऐसी बुकिंग व्यवस्था करनी चाहिए जो हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, मंडी व चंबा के यात्रियों को नियमित रूप से इन ट्रेनों से जोड़ दे। इसी तरह के प्रयास उड़ान के तहत धर्मशाला-शिमला हवाई यात्रा के साथ भी होने चाहिएं। खास तौर पर शिमला एयरपोर्ट पर आने वाली फ्लाइट्स को सफल बनाने के लिए एचआरटीसी ऐसी बस सेवाएं दे, जो यात्रियों की उड़ान की जमीनी स्तर तक पैरवी करे।

राय

कैफे में आतंकी विस्फोट

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू भारत की 'सिलिकॉन वैली' है। वहां के लोकप्रिय 'रामेश्वरम कैफे' में बीते शुक्रवार को ऐसा विस्फोट हुआ, जिसकी नीयत और ताकत आतंकी हमले से कम नहीं थी। विस्फोट में 9 लोग घायल हुए। उनमें 45 साल की एक महिला पहचानी गई, जो सेमीकंडक्टर की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में लेखापाल के पद पर कार्यरत है। वह विस्फोट में झुलस गई है और फिलहाल जख्मों से लड़ रही है। शुरुआती जांच के संकेत हैं कि एक अनजान व्यक्ति ने विस्फोट से कुछ मिनट पहले ही उस लोकप्रिय कैफे में बैग रखा था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, ताकि संदिग्ध की पहचान की जा सके। संभवतः आईईडी विस्फोटक उपकरण उसी बैग में रखा गया था। खान-पान के ऐसे लोकप्रिय स्थलों पर भी सुरक्षा में सुराख देखे गए हैं। वहां पर्याप्त सुरक्षा-व्यवस्था नहीं होती। जबकि ऐसे स्थल ही आतंकी या किसी अन्य हमले के 'आसान लक्ष्य' होते हैं। जांच की कुल 8 टीमें काम कर रही हैं। पुलिस 2022 से उन आतंकी हमलों के साथ इस विस्फोट के संपर्क की संभावनाओं को भी खंगाल रही है, जहां ऐसे ही विस्फोटक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था। राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच का आश्वासन दिया है और अपेक्षा की है कि इस घटना का राजनीतिकरण न किया जाए। विपक्षी भाजपा ने इसे कानून-व्यवस्था की नाकामी करार दिया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान-समर्थक नारों से इस विस्फोट को जोड़ा है। सवाल है कि क्या यह माना जाए कि बेंगलुरू में भी पाकिस्तान के दहशतगर्द तत्त्व और खुफिया एजेंसी आईएसआई पहुंच गए हैं, जिन्होंने ऐसे विस्फोट को अंजाम दिया? वैसे माहौल को गरम और उग्र बनाने में सत्तारूढ़ कांग्रेस का भी योगदान कम नहीं रहा है। उपमुख्यमंत्री ने विस्फोट को 2022 के मंगलूरु विस्फोट से जोड़ दिया, जब राज्य में भाजपा सरकार थी। उपमुख्यमंत्री जैसा जिम्मेदार शख्स यह आरोप किस आधार पर लगा सकता है? उन्होंने इसके विपरीत ही बयान दिया था और राजनीतिकरण न करने का आग्रह किया था। ऐसा दोगलापन ही आतंकी घटनाओं का राजनीतिकरण करता है। राज्य और केंद्र सरकार की अपनी-अपनी एजेंसियां हैं, जिनके दायरे परिभाषित हैं। जांच दलों को अपना काम करने दें। वे ही किसी निष्कर्ष की ओर संकेत कर सकते हैं। दरअसल 'रामेश्वरम कैफे' में यह विस्फोट ज्यादा भयावह इसलिए है, क्योंकि यह वहां स्थित है, जहां आईबीएम, एसएपी सरीखी आईटी कंपनियां और कई स्टार्टअप मौजूद हैं। यह देश का प्रौद्योगिकी केंद्र है। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पेशेवरों के लिए यह कैफे एक लोकप्रिय ठिकाना है। खान-पान के पकवानों के लिए यह विख्यात है। जब दोपहर एक बजे के करीब विस्फोट हुआ, तो कई पेशेवर वहां लंच कर रहे थे। घायलों में वेल्डर, मैकेनिक, बिजली वाले, मिस्त्री आदि 'ब्लू कॉलर' प्रवासी कामगार भी शामिल थे। बेंगलुरू के रेस्टॉरेंट क्षेत्र को अब खुद महसूस करना पड़ेगा कि वे सावधान हो जाएं। अपने ग्राहकों पर निगरानी रखें। एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था तैयार करें। उन्हें अपने स्टाफ को भी प्रशिक्षित करने की जरूरत है, ताकि वे किसी भी संदिग्ध व्यवहार वाले व्यक्ति को पहचान सकें। आपात स्थिति के लिए ऐसे मानदंड भी तैयार किए जाएं, ताकि उनका स्टाफ ग्राहकों को बचा कर सुरक्षित स्थान तक पहुंचा सके। अस्पताल भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि शहर की होटल एसोसिएशन ने कहा है कि वह सुरक्षा-व्यवस्था को सुधारने के लिए एक योजना तैयार करेगी। होटल वाले अपनी एसोसिएशन के सदस्यों और पुलिस से जल्द ही बैठक कर संवाद करेंगे। जाहिर है कि किसी योजना की रूपरेखा पर भी विमर्श होगा। बेंगलुरू में हमने कई बार सांप्रदायिक दंगों की सूरत भी देखी है।

डेस्टिनेशन वेडिंग : प्रदेश के पर्यटन का भविष्य

स्वारघाट, भाखड़ा व पौंग डैम के किनारे सिर्फ डेस्टिनेशन शादियों के लिए समर्पित रिजॉर्ट बनाए जाएं तो पर्यटन के इस क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। प्रदेश की माली हालत को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत निवेश की है। इस निवेश के लिए विदेशों में जाने की जरूरत नहीं है। सरकार चुनिंदा 100 स्थानों पर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए समर्पित रिजॉर्ट के लिए लीज पर भूमि उपलब्ध करवा दे तो निवेश के लिए प्रदेश के उद्यमी मौजूद हैं'

'डेस्टिनेशन वेडिंग' के नाम पर गुजरात के जोड़े ने स्पीति के मोरंग गांव में माइनस 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान में सात फेरे लेकर जहां अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया, वहीं साधारण लोगों के लिए यह 'डेस्टिनेशन वेडिंग' (गंतव्य शादी) शब्द कौतूहल का विषय भी बन गया। साधारण शब्दों मे डेस्टिनेशन वेडिंग वह शादी है जो घर से दूर किसी प्रसिद्ध स्थान में चुनिंदा मेहमानों के साथ आयोजित की जाती है। तेजी से लोकप्रिय होती जा रही इस तरह की शादियों का मुख्य कारण है कि हर किसी का सपना होता है कि वह अपने होने वाले जीवन साथी के साथ किसी ऐसे सुंदर स्थान पर शादी के बंधन मे बंधे, जिससे वह इन पलों को जीवन भर के लिए यादगार बना सके। कोरोना की समाप्ति के पश्चात भारत में डेस्टिनेशन शादियों का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है, आंकड़े यह बताते हैं।

भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग जड़ें उस परम्परा से खोजी जा सकती हैं, जब दो परिवारों के घर दूर शहरों में होने के चलते वर या वधु पक्ष में से कोई एक पक्ष दूसरे के शहर में आकर शादी की रस्मों को निभाते थे। इसके विपरीत विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग का प्रचलन बहुत पहले से शुरू हो गया था। खासकर अमरीका में जहां के युवा जोड़े मैक्सिको या बहमास के समुद्री तटों पर शादियों का आयोजन करके रोमांचित महसूस करते थे। भारत में भी डेस्टिनेशन वेडिंग ने 60 और 70 के दशक में अपने पांव पसारे, पर ज्यादातर यह उच्च वर्गीय लोगों में ही लोकप्रिय थी। धीरे-धीरे आगे बढ़ रही इसकी लोकप्रियता को सोशल मीडिया के जमाने में पंख लग गए जब कुछ मशहूर हस्तियों के डेस्टिनेशन वेडिंग की तस्वीरें लोगों के सामने आने लगी और उनकी देखादेखी मध्यमवर्गीय परिवारों ने भी इसे अपना लिया।

भारत में शादियां कितना बड़ा व्यवसाय बन चुकी हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 'कन्फेडेरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेड्स' के अनुसार नवम्बर 2023 और जून 2024 के बीच भारत में 38 लाख शादियां होंगी जिनमें करीब पौने चार लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इनमें से बहुत बड़ा हिस्सा डेस्टिनेशन शादियों का है। इन शादियों में एक वे लोग हैं जो देश में ही किसी प्रसिद्ध गंतव्य स्थान में शादी को प्राथमिकता देते हैं, दूसरी श्रेणी में वे आते हैं जो विदेशों में शादियां रचाते हैं। वर्ष 2023 में करीब 5000 भारतीयों ने थाईलैंड, तुर्कीए, वियतनाम, अबुधाबी और श्रीलंका जैसे विदेशी गंतव्यों में डेस्टिनेशन शादियों पर करीब 50000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टे विदेशी मुद्रा कोश की ही हानि हुई। इस बात की चिंता माननीय प्रधानमंत्री भी 'मन की बात' के एक एपिसोड में जता चुके हैं।

देश की अर्थव्यवस्था बढऩे से लोगों की आय और खर्च करने की क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई है। भारतीय लोग शादियों में पैसा खर्च करने के लिए दुनिया भर में विख्यात हैं। इस बढ़ी हुई क्षमता का सीधा असर शादियों के आयोजन में देखने को मिल रहा है। एक सर्वे के अनुसार एक उच्च वर्गीय परिवार शादी पर औसतन डेढ़ से दो करोड़ और मध्यमवर्गीय परिवार 20 से 50 लाख रुपए के बीच खर्च करता है। एक शादी के आयोजन में मैरिज पैलेस से लेकर टैंट, केटरिंग, बैण्ड से लेकर कई तरह की तैयारियां करनी पड़ती हैं, पर अगर ये सारी सुविधाएं एक ही स्थान, विशेषकर किसी प्रसिद्ध स्थान पर तय बजट से थोड़े से ज्यादा पैसा खर्च करके मिल रही हों तो लोग ज्यादा पैसा खर्च करने में गुरेज नहीं करते हैं। लोगों की इसी सोच के कारण जयपुर, उदयपुर, गोवा, केरल, अंडेमान निकोबार, आगरा व चंडीगढ़ जैसे विख्यात पर्यटक स्थल डेस्टिनेशन शादियों के केन्द्र के रूप में तेजी से उभर रहे हैं।

देखा जाए तो डेस्टिनेशन वेडिंग पर्यटन का ही एक आयाम है। पर्यटन के क्षेत्र में तो हिमाचल का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, पर देश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में डेस्टिनेशन वेडिंग की तुलना में हिमाचल का हिस्सा नगण्य ही कहा जा सकता है। चंडीगढ़ के नजदीक होने के कारण कसौली इस तरह की शादियों के लिए आदर्श गंतव्य स्थल के रूप में उभरा है, पर अभी भी चंडीगढ़ के बड़े बड़े फार्म हाऊस की तुलना में यह बहुत पीछे है। शिमला के होटल पीटरहॉफ, वुडविले पैलेस, गोल्डन फर्न, कोठी रिजॉर्ट, क्यारी का होटल मेघदूत व धर्मशाला व पालमपुर के कुछ प्रमुख रिजॉर्ट्स में जरूर इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। पर पूरे प्रदेश में जितनी क्षमता है, उससे यह बहुत कम है। डेस्टिनेशन शादियों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि पूरे महीने में एक होटल जितना लाभ कमाता है, इस तरह की शादियों के आयोजन से वह यह पैसा दो दिन में कमा लेता है। इससे इस व्यवसाय से जुड़े स्थानीय डेकोरेटर, फूल वालों, संगीत आदि से जुड़े लोगों को भी निश्चित ही रोजगार मिलता है।

मोरंग में हुई एक डेस्टिनेशन वेडिंग ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अगर हम हिमाचल के स्वच्छ पर्यावरण और अतुलनीय दृष्यावलियों को आधार बना कर मार्केटिंग करें तो यह हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र का नया आधार बन सकता है। स्वारघाट, भाखड़ा व पौंग डैम के किनारे सिर्फ डेस्टिनेशन शादियों के लिए समर्पित रिजॉर्ट बनाए जाएं तो पर्यटन के इस क्षेत्र में क्रांति आ सकती है, क्योंकि इससे उच्च वर्गीय परिवार भी हिमाचल की तरफ आकर्षित होंगे। प्रदेश की माली हालत को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत निवेश की है। और इस निवेश के लिए विदेशों में जाने की जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुनिंदा 100 स्थानों पर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए समर्पित रिजॉर्ट के लिए लीज पर भूमि उपलब्ध करवा दे तो निवेश के लिए प्रदेश के उद्यमी ही आगे आ जाएंगे, पर यह सब सरकार की इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है।

प्रवीण कुमार शर्मा

ये काले काले नाग

हो सकता है आपको इस व्यंग्य के शीर्षक पर ऐतराज़ हो। आप कहें कि शाहरुख़ ख़ान की फिल्म बाज़ीगर के एक गीत में काली-काली आँखों या आमिर ख़ान की फिल्म मन में काली नागिन जैसी ज़ुल्फों की बात की गई है। ऐसे में आप ये काले-काले नाग कहाँ से ले आए। पर ये काले नाग मैंने पैदा नहीं किए। इसके लिए हमें हमाचल के मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवादी होना पड़ेगा, जिन्होंने अपनी पार्टी के छह बाग़ी विधायकों को इस उपाधि से अलंकृत किया है। भला हो उनका, जिन्होंने इस घोर कलियुग में पहली बार अपने नाम के अनुरूप हमें सुख की अनुभूति से सराबोर किया है। वरना देश भर में फैली बेरोजग़ारी, महंगाई, लंगड़ी अर्थव्यवस्था, राष्ट्रवाद और ज़ात-धरम के खेल के इस दौर में ज़माने से अलग सोच रखने वाले मेरे जैसे चंद आदमियों के पास गोदी चिंतन के अलावा करने के लिए अब कुछ शेष नहीं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि रवीश कुमार के गोदी मीडिया के बाद यह गोदी चिंतन कौनसी बला है। तो साधो! गोदी चिंतन अंधभक्ति से उपजा वह चिंतन है, जिसके चलते भारत अगले दो-चार सालों में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है।

इसी अंधचिंतन के सहारे पिछले दस सालों से भारत में नोटबंदी लागू होने के बाद काले धन और आतंकवाद की समस्या दूर हो चुकी है, साँसों को छोडक़र शेष सभी चीज़ों पर जीएसटी लगाया जा चुका है, किसानों की आय दोगुनी हो गई है, सभी बेघरों को पक्के मकान मिल चुके हैं, पेट्रोल-डीज़ल पचास रुपए लीटर मिल रहे हैं और भारत सरकार द्वारा बाईस करोड़ लोगों को रोजग़ार दिए जाने के बाद वे जुमला-नवाज़ की तरह राष्ट्र निर्माण में अपनी सशक्त भूमिका निभा रहे हैं। यह गोदी चिंतन का ही कमाल है कि हमाचल के मुख्यमंत्री ने अपने बाग़ी विधायकों को काले नाग की संज्ञा से अलंकृत किया है। वरना आज़ादी के अमृत काल से गुजऱ रहे देश में इतना संयम किसके पास है कि वह अपने विधायकों को केवल काले नाग कह कर छोड़ दे। जुमला-नवाज़ या तड़ीपार चाणक्य होते तो अपने बागियों का स्वागत ईडी या सीबीआई के हाथों पान पराग से करवाते। दो-चार महीने जेल में उनसे चक्की पीसिंग करवाने के बाद अपने वाशिंग पॉउडर और मशीन में धोने के बाद उन्हें ऐसा सुखाते कि उनसे बग़ावत की सारी सीलन और बदबू ग़ायब हो जाती। मुख्यमंत्री के इस संयमपूर्ण व्यवहार के बावजूद इन बाग़ी विधायकों के तेवर देखिए। कह रहे हैं कि वे अपनी पार्टी के नहीं, सरकार या मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं।

यह तो वही बात हुई कि हमें घर में तो रहना है, पर घर की नींव खोदने का मज़ा भी लेना है। उनके घर अर्थात कांग्रेस पार्टी की दीवारें पहले ही बेरंग और भोथरी हो चुकी हैं। जिस नींव के सहारे पार्टी के रहनुमा घर की रेट्रोफिटिंग की सोच रहे हैं, हमाचल के बाग़ी विधायक उसी नींव को खोदने का मज़ा लेते हुए वृहत हिन्दू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान देना चाहते हैं। उन्हें शायद पता नहीं कि इस पुनीत कार्य के लिए अंधभक्त और गोदी मीडिया ही काफी हैं। हमाचल के मुख्यमंत्री में संयम इतना कूट-कूट कर भरा है कि अपने बाग़ी विधायकों को काले नाग बोलते वक्त उनका गला रूंध गया। लेकिन अगर उन्होंने सारी रेवडियाँ अपनों को देने की बजाय इनमें से कुछ रेवडियाँ बागियों में बाँटी होतीं तो वे भी रेवडियाँ चाटते हुए मुख्यमंत्री और पार्टी के गुण गाते रहते। पर यह मुख्यमंत्री के संयम का ही कमाल है कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को केवल सत्ता का भूखा बताया और अपने बारे में कहा कि उन्हें कुर्सी से अधिक जनता की सेवा का मोह है। पर पता नहीं सभी नेताओं में प्रतिपक्ष में रहते हुए सत्ता की इतनी भूख और सरकार में रहते हुए जनता की सेवा की इतनी चिंता क्यों रहती है। जनता की सेवा के लिए कुरसी इतनी ज़रूरी क्यों है। मुझे तो लगता है कि सत्ता की इस भूख और जनता की सेवा में कोई गहरा सम्बन्ध है जिसकी विवेचना अंधचिंतन से ही संभव है।

पीए सिद्धार्थ

क्या है e-Kisan Upaj Nidhi, किसान कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ?

परिवहन विशेष न्यूज

सरकार किसानों को बिना किसी गारंटी के लिए लोन देने की योजना लाई है- ई-किसान उपज निधि (e-Kisan Upaj Nidhi)। इसे सोमवार को खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया। यह योजना किसान की भंडारण और पैसों की फौरी जरूरत दोनों समस्याओं को हल करेगी। आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार किसानों की तरक्की और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसमें फसल बीमा के साथ पीएम-किसान सम्मान निधि जैसी स्कीम्स हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के साथ उन्हें रियायती दर कर्ज भी दिया जाता है।

अब सरकार किसानों को बिना किसी गारंटी के लिए लोन देने की योजना लाई है- ई-किसान उपज निधि (e-Kisan Upaj Nidhi)। इसे सोमवार को खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया। आइए जानते हैं कि यह योजना क्या है और इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है।

बिना किसी परेशानी के मिलेगा लोन

ई-किसान उपज निधि का मकसद खेती को फायदे का सौदा बनाना है। इस स्कीम के तहत किसान वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) के पास रजिस्टर्ड गोदामों में अपनी फसल रखकर लोन ले सकेंगे। उन्हें अलग से कुछ भी गारंटी यानी गिरवी रखे बिना 7 प्रतिशत की ब्याज पर आसानी से लोन मिल सकेगा।

रकम और ब्याज चुनने का विकल्प भी

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने योजना लॉन्च करते समय बताया कि इस डिजिटल प्लेटफार्म से जुड़े बैंक किसानों को कर्ज की रकम और ब्याज दर चुनने का भी विकल्प देंगे। अभी WDRA के पास करीब 5,500 गोदाम रजिस्टर्ड हैं। वहीं, खेती से जुड़े गोदामों की संख्या एक लाख है। गोयल ने कहा कि गोदाम मालिकों से ली जाने वाली सुरक्षा राशि को भी स्टॉक वैल्यू के तीन फीसदी से घटाकर एक फीसदी किया जाएगा।

कम दाम पर उपज बेचने की मजबूर खत्म

किसान अक्सर भंडारण की सही बंदोबस्त ना होने की वजह से अपनी उपज को औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। कई बार उन्हें नई फसल की बुआई के लिए पैसों की जरूरत होती है। लिहाजा, वे मजबूरन कम कीमत में उपज बेच देते हैं।

ई-किसान उपज निधि से उनकी भंडारण और पैसों की फौरी जरूरत, दोनों परेशानियों का इलाज हो जाएगा। वे अपनी उपज को गोदाम में रखकर कर्ज ले सकेंगे। और फिर जब उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी, तो वे फसल बेचकर अपना कर्ज आसानी से चुका भी सकेंगे।

वृद्धि को प्रभावित कर सकती है बहुत अधिक नियामकीय घेराबंदी: उदय कोटक

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के दो दिवसीय कार्यक्रम में दिग्गज बैंक उदय कोटक ने कहा कि ज्यादा नियामकीय घेराबंदी आर्थिक वृद्धि को बाधित करने के साथ एक विकसित राष्ट्र की ओर भारत की यात्रा को बाधित कर सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 7.5-8 प्रतिशत की तेज वृद्धि दर हासिल करने के लिए रचनात्मकता उद्यमिता और पेशेवर भावना की जरूरत है।

नई दिल्ली। दिग्गज बैंकर उदय कोटक ने मंगलवार को कहा कि बहुत अधिक नियामकीय घेराबंदी आर्थिक वृद्धि को बाधित कर सकती है और एक विकसित राष्ट्र की ओर भारत की यात्रा को बाधित कर सकती है। उन्होंने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के दो दिवसीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नियामकों को बहुत अधिक रूढ़िवादी और सतर्क नहीं होना चाहिए।

इसकी जगह संबंधित क्षेत्रों में किसी आकस्मिक घटना पर तेजी से प्रतिक्रिया देनी चाहिए।उन्होंने कहा, 'मैं भारत के भविष्य के बारे में बहुत आशावादी हूं, लेकिन मैं इस बात को लेकर भी बहुत सचेत हूं कि, घेराबंदी के बिना अवसरों को पाने की बेलगाम कोशिश जोखिम पैदा कर सकती है और इसी तरह बहुत अधिक घेराबंदी से भी हम वहां (विकसित देश) तक नहीं पहुंच पाएंगे।' अगले 20-25 वर्षों में 7.5-8 प्रतिशत की तेज वृद्धि दर हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण जरूरी है। इसके लिए रचनात्मकता, उद्यमिता और पेशेवर भावना की जरूरत है। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलना है तो हमें अपनी अपनी उद्यमशीलता और रचनात्मक भावनाओं की रक्षा और पोषण करने की बहुत जरूर है।

वृद्धि के लिए व्यावसायिक सत्यनिष्ठा महत्वपूर्ण: एनसीएलएटी चेयरमैन

अपीलीय न्यायाधिकरण राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के चेयरमैन न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने मंगलवार को कहा कि आर्थिक वृद्धि के लिए व्यावसायिक सत्यनिष्ठा बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कंपनियों की पहली जिम्मेदारी ऐसे बहीखातों को तैयार करने की है, जिन पर भरोसा किया जा सकता है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि लगातार सतर्कता बरतने की जरूरत है ताकि पारदर्शिता और शासन व्यवस्था का प्रत्येक ठीक से और पूरी क्षमता से काम करे। उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय स्थिति निष्पक्ष रूप से नहीं बताई गई, तो संस्थानों और निवेशकों से पैसा जुटाना मुश्किल हो जाता है।

2023 में घटकर 3.1 प्रतिशत रह गई बेरोजगारी दर, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट से जानकारी मिली कि 15 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 2023 में घटकर 3.1 प्रतिशत रह गई जो पिछले तीन वर्षों में सबसे कम है। महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर भी 2022 में 3.3 प्रतिशत से घटकर 2023 में 3 प्रतिशत हो गई। पुरुषों के लिए 2022 में 3.7 से घटकर 2023 में 3.2 प्रतिशत हो गई।

नई दिल्ली। सांख्यिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन(नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 15 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 2023 में घटकर 3.1 प्रतिशत रह गई, जो पिछले तीन वर्षों में सबसे कम है। कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार, बेरोजगारी दर 2022 में 3.6 प्रतिशत और 2021 में 4.2 प्रतिशत से घटकर 2023 में 3.1 प्रतिशत हो गई। बेरोजगारी या बेरोजगारी दर, को श्रम बल में बेरोजगार लोगों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

महामारी के बाद आई स्थिति में सुधार

आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2020 में देश में महामारी की चपेट में आने के बाद रोजगार की स्थिति में सुधार हो रहा है, जिसने अधिकारियों को घातक कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर किया। आंकड़ों में केंद्र और राज्यों द्वारा लॉकडाउन हटाने के बाद आर्थिक गतिविधियों में उछाल में सुधार भी दिखाया गया है।

क्या कहते हैं आंकड़े

सर्वे से पता चला कि महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर भी 2022 में 3.3 प्रतिशत और 2021 में 3.4 प्रतिशत से घटकर 2023 में 3 प्रतिशत हो गई। इसी तरह पुरुषों के लिए, यह 2022 में 3.7 प्रतिशत और 2021 में 4.5 प्रतिशत से घटकर 2023 में 3.2 प्रतिशत हो गई। जहां शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की कुल दर 2022 में 5.7 प्रतिशत और 2021 में 6.5 प्रतिशत से घटकर 2023 में 5.2 प्रतिशत हो गई।

इनसाइड

सोना- चांदी के नए दाम हुए जारी, फटाफट चेक करें कितना महंगा-सस्ता हुआ गोल्ड

गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट रेट्स जारी हो गए हैं। मंगलवार के कारोबारी दिन सोना और चांदी की वायदा कीमतों में उछाल दर्ज हुआ है। मंगलवार के कारोबारी दिन सोने की वायदा कीमत में उछाल दर्ज हुआ है। सोने की कीमत 80 रुपये उछलकर 64542 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी की वायदा कीमत की बात करें तो यह 371 रुपये बढ़ी है।

नई दिल्ली। मंगलवार के कारोबारी दिन के लिए सोना-चांदी की नई कीमतें जारी हो गई हैं। सोना-चांदी की वायदों कीमतों की ही बात करें तो आज सोना और चांदी दोनों के ही भाव चढ़े हैं। मंगलवार के कारोबारी दिन सोने की वायदा कीमत में उछाल दर्ज हुआ है। सोने की कीमत 80 रुपये उछलकर 64,542 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, अप्रैल डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 80 रुपये या 0.12 प्रतिशत बढ़कर 64,542 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 16,232 लॉट का कारोबार हुआ।

वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में सोना वायदा 0.07 प्रतिशत बढ़कर 2,127.70 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस हो गया। वायदा कारोबार में मंगलवार को चांदी की कीमत 371 रुपये बढ़कर 73,838 रुपये प्रति किलोग्राम हो गयी।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, मई डिलीवरी के लिए चांदी अनुबंध 561 लॉट में 371 रुपये या 0.5 प्रतिशत बढ़कर 73,838 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया।

2023 में महिलाओं ने लिया 19 प्रतिशत ज्यादा लोन, 30.95 लाख करोड़ रुपये पहुंची बकाया राशि

परिवहन विशेष न्यूज

2023 में महिलाओं की ओर से लिए गए लोन में 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही है। इस दौरान कुल लोन वितरण में 17 प्रतिशत की वृद्धि रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में महिलाओं पर बकाया कुल लोन की राशि बढ़कर 30.95 लाख करोड़ रुपये रही है जो 2022 में 26 लाख करोड़ रुपये थी। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। 2023 में महिलाओं की ओर से लिए गए लोन में 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही है। इस दौरान कुल लोन वितरण में 17 प्रतिशत की वृद्धि रही है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले क्रेडिट इन्फार्मेशन कंपनी क्रिफ हाई मार्क की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष पर्सनल और दोपहिया पोर्टफोलियो लोन में 26 प्रतिशत की सबसे ज्यादा वृद्धि रही है।

30.95 लाख करोड़ रुपये पहुंची बकाया लोन की राशि

रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में महिलाओं पर बकाया कुल लोन की राशि बढ़कर 30.95 लाख करोड़ रुपये रही है जो 2022 में 26 लाख करोड़ रुपये थी। पिछले वर्ष कारोबारी और शिक्षा लोन को छोड़कर सभी श्रेणियों में महिलाओं को लोन वितरण में वृद्धि रही है।

कारोबारी और शिक्षा लोन में आई कमी

महिलाओं को कारोबारी और शिक्षा लोन में क्रमशः 19 व 1 प्रतिशत की कमी रही है। पिछले वर्ष महिलाओं को पर्सनल लोन में 52 प्रतिशत और संपत्ति गिरवी रखकर लोन लेने में 39 प्रतिशत की वृद्धि रही है। 2023 में महिलाओं पर बकाया पर्सनल लोन की राशि 26 प्रतिशत बढ़कर 12.76 लाख करोड़ रुपये रही है।

पिछले वर्ष आरबीआइ ने पर्सनल लोन जैसे असुरक्षित लोन को लेकर चिंता जताई थी। साथ ही ऐसे लोन पर आरबीआइ ने बैंकों के लिए जोखिम भार को बढ़ा दिया था। उद्योग से जुड़े लोगों के अनुसार, पिछले वर्ष बड़ी संख्या में संभावित जोखिम वाले 50 हजार रुपये से कम के लोन वितरित किए गए हैं। 2023 में महिलाओं को पर्सनल लोन का औसत आकार 80 हजार रुपये रहा है, जो 2022 में एक लाख रुपये था। हालांकि, अन्य श्रेणी में औसत लोन आकार की राशि में 2023 में वृद्धि रही है।

अप्रैल-फरवरी के दौरान 88 करोड़ टन कोयले का उत्पादन, चालू वित्त वर्ष में हुई 12 प्रतिशत की वृद्धि

परिवहन विशेष न्यूज

कोयला मंत्रालय ने मंगलवार को बयान में बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 के मुकाबले चालू वित्त वर्ष में कोयला उत्पादन में 12 प्रतिशत की वृद्धि रही है। मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष फरवरी में कोयला उत्पादन 12 प्रतिशत बढ़कर 9.66 करोड़ टन रहा है जो पिछले वर्ष समान अवधि में 8.63 करोड़ टन रहा था। चालू वित्त वर्ष में फरवरी तक कुल कोयला आपूर्ति 11 प्रतिशत बढ़ी है।

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल-फरवरी के दौरान भारत का कोयला उत्पादन 88.07 करोड़ टन रहा है। अब पूरे वित्त वर्ष में 100 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने में 11.92 करोड़ टन की कमी रह गई है। पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 89.3 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ था।

दर्ज हुई 12 प्रतिशत की वृद्धि

कोयला मंत्रालय ने मंगलवार को बयान में बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 के मुकाबले चालू वित्त वर्ष में कोयला उत्पादन में 12 प्रतिशत की वृद्धि रही है। मंत्रालय के अनुसार, इस वर्ष फरवरी में कोयला उत्पादन 12 प्रतिशत बढ़कर 9.66 करोड़ टन रहा है जो पिछले वर्ष समान अवधि में 8.63 करोड़ टन रहा था।

फरवरी में कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन आठ प्रतिशत बढ़कर 7.47 करोड़ टन रहा है। चालू वित्त वर्ष में फरवरी तक कुल कोयला आपूर्ति 11 प्रतिशत बढ़कर 88.24 करोड़ टन रही है, जो पिछले वर्ष समान अवधि में 79.44 करोड़ टन रही थी। ये उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को समर्थन देने के लिए स्थिर कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने में सभी हितधारकों के ठोस प्रयासों को रेखांकित करती हैं। चूँकि राष्ट्र आत्मनिर्भरता और सतत विकास के दृष्टिकोण का अनुपालन कर रहा है, इसलिए कोयला उद्योग विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के प्रति अपने समर्पण में मजबूती से खड़ा है।

पेटीएम और IIFL फाइनेंस के बाद अब RBI के निशाने पर जेएम फाइनेंसिशयल, शेयर-डिबेंचर्स के बदले लोन देने पर लगाई रोक

परिवहन विशेष न्यूज

रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक और IIFL फाइनेंस के बाद अब इन्वेस्टमेंट कंपनी जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। उसने कंपनी पर शेयर और डिबेंचर्स (Debentures) के बदले कर्ज देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आरबीआई को कंपनी के IPO फाइनेंसिंग और NCD (नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर) सब्सक्रिप्शन में गड़बड़ी मिली। जानिए पूरा मामला।

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक और IIFL फाइनेंस के बाद अब इन्वेस्टमेंट कंपनी जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। बैंकिंग रेगुलेटर ने जेएम फाइनेंशियल पर शेयर और डिबेंचर्स (Debentures) के बदले कर्ज देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

जेएम फाइनेंशियल के खिलाफ एक्शन क्यों?

RBI ने एक बयान में कहा कि जेएम फाइनेंशियल के कामकाज में बड़ी खामियां पाई गई हैं। इसकी IPO फाइनेंसिंग और NCD (नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर) सब्सक्रिप्शन में गड़बड़ी मिली। अब कंपनी IPO और डिबेंचर्स सब्सक्रिप्शन के लिए भी फाइनेंसिंग नहीं कर सकेगी। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने कहा कि जेएम फाइनेंशियल कलेक्शन और वसूली प्रक्रिया के जरिए अपने मौजूदा लोन खातों से जुड़ी एक्टिविटीज जारी रख सकती है।

स्पेशल ऑडिट के बाद होगी पाबंदी की समीक्षा

RBI ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से मिली जानकारी के आधार पर कंपनी के बहीखातों का रिव्यू किया। इसमें गड़बड़ी का पता चला। बैंकिंग रेगुलेटर ने कहा कि अब जेएम फाइनेंशियल का एक स्पेशल ऑडिट होगा। अगर बैंक कंपनी के उठाए कदमों से संतुष्ट होता है, तो पाबंदियों की समीक्षा की जाएगी।

क्या है जेएम फाइनेंशियल के शेयरों का हाल

जेएम फाइनेंशियल के शेयर मंगलवार को 2 प्रतिशत की गिरावट के साथ 95.50 रुपये पर बंद हुआ। इसने पिछले एक साल अपने निवेशकों को करीब 50 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। अब देखना होगा कि आरबीआई के एक्शन के बाद कंपनी के निवेशक क्या रुख अपनाते हैं।

इससे पहले पेटीएम, IIFL फाइनेंस पर एक्शन

रिजर्व बैंक ने इससे पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक और IIFL फाइनेंस के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया था। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को तो आरबीआई ने 15 मार्च अपना कामकाज बंद करने को कहा है। वहीं, IIFL फाइनेंस पर नए गोल्ड लोन बांटने की रोक लगी है।

बिटकॉइन में फिर आया बंपर उछाल, साल भर में 200 प्रतिशत बढ़ा भाव, जानिए और कितना बढ़ेंगी कीमतें

नवंबर में रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंचने के बाद बिटकॉइन की कीमतों में गिरावट आनी शुरू हुई। दुनियाभर में इसे लेकर नियम सख्त होने लगे। भारत में भी 2022 के आम बजट में क्रिप्टो ट्रेडिंग से होने वाले लाभ पर 30 प्रतिशत टैक्स लगा दिया गया था। इन सबके चलते क्रिप्टोकरेंसी मार्केट एकदम से डाउन हो गया। लेकिन अब निवेशक फिर से इस डिजिटल एसेट का रुख कर रहे हैं।

नई दिल्ली। दुनिया की सबसे मशहूर और बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन (Cryptocurrency Bitcoin) का जादू एक बार फिर लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। पिछले काफी समय से बिटकॉइन की कीमत ढलान पर थी। लेकिन, हाल के दिनों में इसमें काफी तेजी नजर आ रही है। सोमवार को तो ट्रेड के दौरान बिटकॉइन 68,791 डॉलर के स्तर पर पहुंच गई थी। यह उसके ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड के करीब है, जो उसने 10 नवंबर 2021 को बनाया था। उस समय बिटकॉइन की कीमत 68,789 डॉलर थी। लेकिन, उसके बाद बिटकॉइन का बुरा दौर शुरू हुआ। रेगुलेटरी अनिश्चितताओं के चलते इसकी प्राइस में लगातार गिरावट आई। जुलाई 2022 में तो बिटकॉइन की कीमत घटकर 20,547.81 डॉलर तक आ गई। इसी साल जनवरी की बात करें, तो बिटकॉइन की कीमत 42,034 डॉलर थी। लेकिन, सिर्फ पांच दिनों में इसमें करीब 20 प्रतिशत का उछाल आया और यह 60 हजार डॉलर के स्तर तक पहुंच गई। तभी से यह लगातार उसी स्तर के आसपास बना हुआ है। हालांकि, मंगलवार को मुनाफावसूली के चलते इसमें गिरावट आई और यह 0.68 प्रतिशत फिसलकर 67,876.60 डॉलर (55,07,277.98 रुपये) पर आ गया।

मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने उज्जैन - जावरा फोरलेन 102.80 किमी सड़क मार्ग की स्वीकृति दी, 5 हजार 17 करोड़ से ज्यादा का होगा खर्च

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। डॉ राजेंद्र पांडेय विधायक द्वारा लगातार की जा रही जावरा-उज्जैन सड़क मार्ग को फोर लेन सड़क मार्ग किये जाने की स्वीकृति प्रदेश के मंत्री परिषद की बैठक में दे दी गयी। मंत्री परिषद द्वारा **उज्जैन को जावरा स्थित एक्सप्रेस-वे इंटरचेंज से जोड़ने के लिये 102.80 किमी लम्बे ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाइवे के निर्माण की स्वीकृति दी है।** इस परियोजना का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हाइब्रिड एनयूटी आधार पर होगा। परियोजना की लागत 5 हजार 17 करोड़ 22 लाख रूपए है।

परियोजना पर 17 वर्षों में कुल व्यय 5 हजार 17 करोड़ 22 लाख रूपए में से 557 करोड़ रूपए का भुगतान सड़क विकास निगम और 4460 करोड़ रूपए का भुगतान राज्य बजट से किया जायेगा।

इस मार्ग पर 7 बड़े पुल, 26 छोटे पुल, 270 पुलिया, 5 फ्लाई ओवर, 2 रेलवे ओवरब्रिज बनाये जाएंगे। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिल्ली एवं मुम्बई के मध्य 8 लेन एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है।

इस राजमार्ग की 247 कि.मी. लम्बाई राज्य के मंदसौर, रतलाम एवं झाबुआ जिलों से गुजरता है। एक्सप्रेस- वे के इस भाग में 7 स्थानों पर एक्सप्रेस-वे से जुड़ने के लिये इंटरचेंज दिये गये हैं। इनमें से एक इंटरचेंज जावरा के पास भूतेड़ा पर स्थित है। क्षेत्र के औद्योगिक विकास एवं अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार को दृष्टिगत रखते हुये उज्जैन शहर को जावरा स्थित एक्सप्रेस-वे इंटरचेंज से जोड़ने के लिये यह निर्णय लिया गया है। इस फोर लेन सड़क मार्ग के लिए विधायक डॉ पांडेय ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से कई बार आग्रह किया था।

प्रदेश शासन व विधानसभा में भी इस मार्ग के लिए बात उठाई थी।

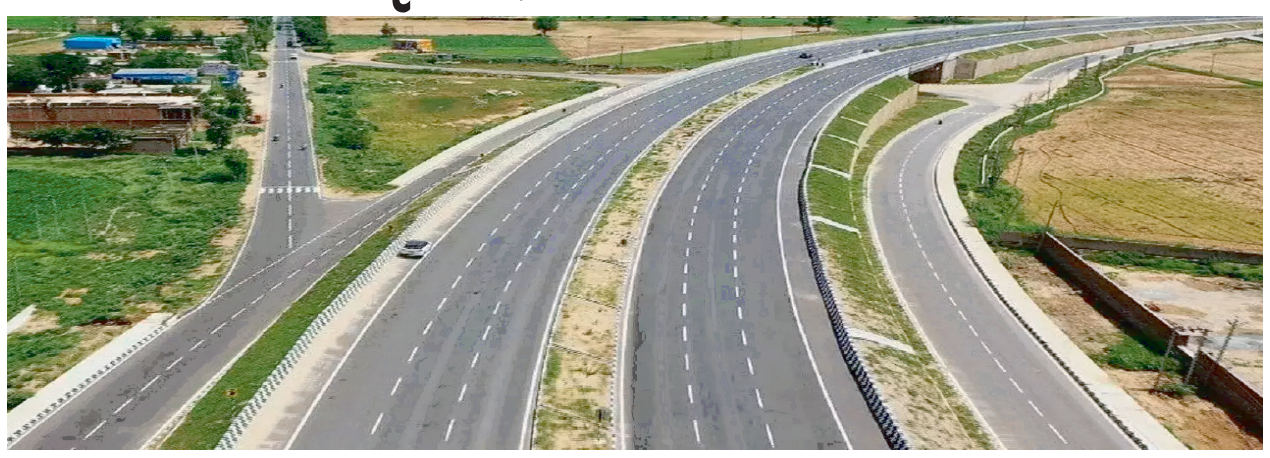

34 KM का सफर... 8 स्टेशन, गाजियाबाद में नए रूट पर चलेगी रैपिड ट्रेन; चुनाव से पहले PM मोदी का तोहफा

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कारिडोर के 17 किमी लंबे अतिरिक्त सेक्शन का आज उद्घाटन होगा। ट्रेन मुरादनगर व मोदीनगर में नार्थ व साउथ स्टेशन पर ठहरेगी। इसके बाद नमो भारत ट्रेन की सेवा 34 किमी के सेक्शन पर निर्बाध रूप से उपलब्ध हो जाएगी। 34 किमी के रूट पर कुल 8 स्टेशन हैं। इस रूट पर रैपिड ट्रेन के संचालन से लोगों के समय की बचत होगी। उन्हें लाभ मिलेगा।

मोदीनगर। मोदीनगर-मुरादनगर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। इस रूट पर बुधवार से नमो भारत ट्रेन दौड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 किमी लंबे इस रूट का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इसको लेकर लोगों में उत्साह है। तीनों स्टेशनों को फूलों से सजाया गया है।

2019 में शुरू हुआ था काम

नमो भारत ट्रेन के संचालन से मोदीनगर से गाजियाबाद के बीच की दूरी कुछ ही मिनटों में तय हो सकेगी। लोगों के समय की बचत होगी। उन्हें लाभ मिलेगा। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का काम मार्च 2019 से शुरू हुआ था। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके प्रायोरिटी सेक्शन का शुभारंभ किया। जिसमें दुहाई तक नमो भारत ट्रेन का संचालन शुरू हुआ।

रोजाना लोग इसपर सफर भी कर रहे हैं। तभी से अगले सेक्शन को शुरू करने पर आरआरटीएस की तैयारी चल रही थी, जिसमें मोदीनगर तक ट्रेन शुरू होनी थी। इसको लेकर दिन-रात काम चला। अब कार्य पूरा हो गया है। बुधवार से मुरादनगर-मोदीनगर के लोगों को नमो भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी।

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कारिडोर के 17 किमी लंबे अतिरिक्त सेक्शन का आज उद्घाटन होगा। ट्रेन मुरादनगर व मोदीनगर में नार्थ व साउथ स्टेशन पर ठहरेगी। नमो भारत ट्रेन की सेवा 34 किमी के सेक्शन पर निर्बाध रूप से उपलब्ध हो जाएगी।

रूट पर हैं कुल आठ स्टेशन

इस रूट पर कुल आठ स्टेशन हैं। साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, दुहाई डिपो, मुरादनगर, मोदीनगर नार्थ और मोदीनगर साउथ। मोदीनगर से बड़ी संख्या में लोग रोजाना गाजियाबाद, साहिबाबाद व इंदिरापुरम नौकरी के लिए जाते हैं। ऐसे में उन्हें रास्ते में जाम में फंसकर परेशान होना पड़ता है। अब नमो भारत ट्रेन शुरू से लोग कुछ ही देर में यह दूरी का तय कर सकेंगे। दुहाई तक ट्रेन शुरू होने के बाद से ही लोग मोदीनगर तक शुरू होने की आस लगाए थे।

शंकरलाल जाट सांगवा भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष मनोनीत

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देशानुसार किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भागीरथ चौधरी ने भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की सहमति से शंकरलाल जाट सांगवा को किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है और अतिशीघ्र अपनी जिला कार्यकारिणी के गठन एवं जिले के सभी मंडलों में अध्यक्षों की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि जाट वर्तमान में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं और इससे पूर्व सहाड़ा विधानसभा के सह संयोजक, भाजपा में जिला मंत्री व किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सहित विभिन्न पदों पर रहते हुए कार्य कर चुके हैं।

आवाज़ सच की सांझा मोर्चा ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर अध्यक्ष सुरिंदर कुमार सोनू के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय में बैठक की

अमृतसर (साहिल बेरी)। इस मौके पर ज्वाइंट कमिश्नर सुरिंदर सिंह के साथ मीटिंग होनी थी, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण सुपरिंटेंडेंट सतपाल ने यूनियन के सदस्यों के साथ मीटिंग की और उन्हें आश्वासन दिया कि वह जल्द ही ज्वाइंट कमिश्नर के साथ मीटिंग करवाएंगे। कुछ दिन। इस मौके पर बोलते हुए अध्यक्ष सुरिंदर कुमार सोनू ने कहा कि अगर आने वाले दिनों में उनकी मांगों पर बैठक नहीं हुई तो कर्मचारी संगठन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस मौके पर विभिन्न संगठनों के कर्मचारी भी मौजूद थे।

सीएम योगी का ग्रेटर नोएडा को बड़ा तोहफा, बोड़ाकी तक मेट्रो विस्तार को मंजूरी

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रेटर नोएडा में मेट्रो के इस विस्तार के लिए 416 .34 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। करीब 2 .6 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड ट्रैक पर दो स्टेशन जुनपत और बोड़ाकी होंगे। इससे दादरी ग्रेनो व नोएडा से दिल्ली तक के लिए सीधी कनेक्टिविटी होगी। अभी दादरी के लोग अलग अलग साधनों से ग्रेनो व नोएडा जाते हैं जबकि कुछ लोग गाजियाबाद होते हुए नोएडा जाते हैं।

ग्रेटर नोएडा। बोड़ाकी में प्रस्तावित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के विकास को तेज गति देने के लिए अब बोड़ाकी तक मेट्रो की कनेक्टिविटी को हरी झंडी मिल गई है। प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में नोएडा के सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा के जैतपुर स्थित डिपो तक चलने वाली एक्वा मेट्रो अब बोड़ाकी तक के लिए स्वीकृति दे दी है। मेट्रो के इस विस्तार के लिए 416.34 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। करीब 2.6 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड ट्रैक पर दो स्टेशन जुनपत और बोड़ाकी होंगे। इस रूट के बनने से दादरी और बोड़ाकी के आसपास से नोएडा ग्रेनो और आने वाले समय में दिल्ली के बीच सफर करने वाले लाखों यात्रियों को सहूलियत मिलेगी।

बोड़ाकी में बनेगा मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब

ग्रेटर नोएडा के बोड़ाकी में मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनना है। यहां पर अंतरराज्यीय बस अड्डा, रेल, मेट्रो की सुविधाएं विकसित होंगी। डिपो स्टेशन से बोड़ाकी तक मेट्रो विस्तार के लिए पूर्व में ही डीपीआर तैयार हो गई थी, लेकिन हर बार बजट को लेकर मामला अटक जाता था। वर्तमान में एक्वा मेट्रो नोएडा के सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा के जैतपुरा गांव स्थित डिपो स्टेशन तक चलती है।

अब बोड़ाकी तक मेट्रो की लाइन बिछेगी। इससे दादरी, ग्रेनो व नोएडा से दिल्ली तक के लिए सीधी कनेक्टिविटी होगी। अभी दादरी के लोग अलग अलग साधनों से ग्रेनो व नोएडा जाते हैं, जबकि कुछ लोग गाजियाबाद होते हुए नोएडा जाते हैं। अलीगढ़ से आने वाले लोग बोड़ाकी ट्रेन से उतरकर सीधे मेट्रो लेकर नोएडा और ग्रेनो जा सकेंगे।

शुरू में चार कोच की चलेगी मेट्रो

शुरुआत में मेट्रो संचालन में कम खर्च को ध्यान में रखते हुए बोड़ाकी तक चार कोच की मेट्रो चलेगी। जानकारी के मुताबिक रूट पर यात्रियों की संख्या बढ़ने के बाद मेट्रो कोच की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।

बोडाकी के आस-पास के गांव चिटेहरा, दतावली कटहेरा, और पल्ला गांव को लाभ मिलेगा। इन गांवों की जमीन पर मल्टीमॉडल टांसपोर्ट हब, मल्टी मॉडल लाजिस्टिक हब, इंटिग्रेटेड इंडसट्रियल टाउनशिप बसाई जा रही है। बोड़ाकी के आसपास सात गांवों की 478 हेक्टेयर जमीन पर यह परियोजनाएं विकसित होंगी। अब तक करीब 80 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण हो गया है।

मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब से होगा विकास

बोड़ाकी में मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब प्रस्तावित है। यहां रेलवे टर्मिनल भी बनेगा। इसके बनने के बाद ग्रेटर नोएडा व उसके आसपास रहने वालों को पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के लिए ट्रेनें यहीं से मिल जाएंगी। उन्हें नई दिल्ली और गाजियाबाद नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा अंतरराज्यीय व स्थानीय बस अड्डा बनेगा। मेट्रो की कनेक्टिविटी भी होगी। इस हब में होटल भी बनेंगे। ऐसे में क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी।

स्क्रिप्ट का काम पूरा, फिल्म सिटी निर्माण पर अब होगा एक्शन; 230 एकड़ में मिलेंगी सभी सुविधाएं

यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में फिल्म सिटी परियोजना एक हजार एकड़ में प्रस्तावित है। फिल्म सिटी के पहले चरण के विकास पर 1510 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। 230 एकड़ में सात जोन में फिल्म सिटी को विकसित किया जाएगा। इसमें प्रशासनिक एवं क्रिएटिव हब दस एकड़ में होगा।

ग्रेटर नोएडा। कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदेश की पहली फिल्म सिटी के विकासकर्ता चयन पर अपनी मुहर लगा दी। शासनादेश जारी होने के बाद यमुना प्राधिकरण विकासकर्ता कंपनी को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करेगा। फिल्म सिटी के पहले चरण के विकास पर 1510 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सैकड़ों लोगों को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। तीन साल में फिल्म सिटी विकसित होगी।

प्राधिकरण ने 1400 पिलर लगाकर फिल्म सिटी की जमीन को सुरक्षित कर दिया है। फिल्म निर्माता निर्देशक बोनी कपूर और भूटानी समूह की कंपनी बेव्यू प्रोजेक्टस ने 18 प्रतिशत की सबसे ऊंची बोली लगाकर फिल्म सिटी की निविदा अपने नाम की थी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में गठित सचिव समिति की स्वीकृति के बाद मंगलवार को प्रदेश कैबिनेट ने भी विकासकर्ता कंपनी बेव्यू प्रोजेक्टस के नाम पर अपनी स्वीकृति दे दी है।

230 एकड़ में बनेगी फिल्म सिटी यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में फिल्म सिटी परियोजना एक हजार एकड़ में प्रस्तावित है। बेव्यू प्रोजेक्टस को पहले चरण में 230 एकड़ में फिल्म सिटी विकसित करने के लिए चयनित किया गया है। 230 एकड़ में सात जोन में फिल्म सिटी को विकसित किया जाएगा। इसमें प्रशासनिक एवं क्रिएटिव हब दस एकड़ में होगा।

प्रोडक्शन स्टूडियो 60 एकड़, आवासीय एवं अन्य सुविधाएं 20 एकड़, फैक्ट्री व क्राफ्टमैनशिप 15एकड़, मनोरंजन जोन 35 एकड़, फिल्म यूनिवर्सिटी बीस एकड़ व कमर्शियल एरिया 70 एकड़ में होगा। विकासकर्ता को 90 साल के लिए फिल्म सिटी संचालन का लाइसेंस दिया गया है।

एक ही स्थान पर फिल्म निर्माण की सभी सुविधाएं फिल्म सिटी में फिल्म निर्माण की सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर विकसित होंगी

ध्वनि व प्रकाश के विशेष प्रभाव वाला स्टूडियो

शूटिंग के लिए देश के धार्मिक स्थल

प्रमुख ऐतिहासिक स्थल के सेट

जिला कलक्टर ने ली विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक

- विभागीय योजनाओं सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा कर दिये प्रभावी दिशा - निर्देश
- शहर वासी खुले में नहीं फैला पाएंगे गंदगी, आधुनिक कैमरों से रखी जाएगी नजर

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

शाहपुरा। जिला कलक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने मंगलवार को ज़िला कलेक्ट्रेट सभागार में ज़िले के विभिन्न विभागीय अधिकारियो के साथ बैठक लेकर विभागीय योजनाओं एवं 100 दिवसीय कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा - निर्देश दिये। बैठक में जिला कलक्टर शेखावत ने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी जनकल्याणकारी योजनाओं की जिले में भौतिक प्रगति, लाभार्थियों की संख्या, योजनाओं के तहत लाभार्थियों को प्राप्त सब्सिडी सहित विभिन्न बिंदुओं व 100 दिवसीय कार्य योजना के निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा कर संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। साथ ही जिला कलक्टर शेखावत ने नवगठित ज़िले शाहपुरा के सौंदरीकरण तथा उचित साफ़ सफ़ाई के संबंध में चर्चा करते हुए शहर में आधुनिक कैमरा कंट्रोल सिस्टम लगवाकर सर्विलेंस करवाने का निर्णय लिया जिस से शहर में अनुचित रूप से गंदगी फैलाने वालों का चालान काटा जा सके। ज़िला कलेक्टर ने शहर की साफ़ - सफ़ाई उचित रूप से करवाने हेतु जल्द ही नवगठित ज़िले शाहपुरा में आधुनिक स्वीपिंग मशीन (कोब्लर/लिटर पिकर) द्वारा सफ़ाई शुरू करने का निर्णय लेते हुए नगर परिषद आयुक्त को इस संबंध में दिशा निर्देश दिये। शहर के सौंदरीकरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से ज़िला कलेक्टर शेखावत ने शहर की सार्वजनिक दिवारो पर आकर्षक रंगरोगन करवाने तथा पर्याप्त मात्रा में पौधे लगवाने के लिए नगर परिषद आयुक्त तो प्रभावी निर्देश दिये। बैठक के दौरान फूलडोल मेले की पूर्व तैयारियों की विस्तार से समीक्षा करते हुए ज़िला कलेक्टर ने कहा कि बिजली, पानी और सड़क एवं सुरक्षा से जुड़े विभाग जल्द से जल्द समस्याओं को दूर करें जिससे कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। इस दौरान बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश कुमार मीना सहित सभी संबंधित ज़िला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

शताब्दी के युगपुरस बीजू पटनायक

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेस्वर् : किलिंगबीर् बीजू पटनायक एक मजबूत और प्रमुख नस्लवादी व्यक्ति थे। उनका नाम लेते ही रुढ़िवादियों की आंखों के सामने शिखर पर पहुंच चुके एक जिंदादिल इंसान की छवि नाचने लगती है। मैदान पर फुटबॉल खेलने से लेकर आकाश में हवाई जहाज उड़ाने तक, वह बहादुर, निर्भीक और साहसी थे। अपने घटनापूर्ण जीवन में, बचपन से ही उन्होंने वो काम किए हैं जो केवल वे ही कर सकते थे और इसी वजह से उनकी बहादुरी, निडरता और देशभक्ति के इर्द-गिर्द कई कहानियाँ और किंवदंतियाँ बनाई गई हैं। 1923 की घटना, वह सात साल का लड़का था। कई दिनों तक पेट में दर्द रहता है। धीरे-धीरे दर्द बढ़ने लगा और असहनीय होने पर मां आशालता देवी और पिता लक्ष्मीनारायण पटनायक चिंतित हो गये। बेटे को अस्पताल ले जाने पर पता चला कि उसका अपेंडिक्स फट गया है, जिसके लिए तुरंत सर्जरी की जरूरत है। लेकिन वहां बचाव के उपाय नहीं होने से ड्यूटी डॉक्टर चिंतित हो गये। उन्हें इस बात की चिंता थी कि बच्चा बिना किसी निश्चितता के ऑपरेशन से बच पाएगा या नहीं। वह इसे सहन कर पाएगा या नहीं यह उसके लिए चिंता का कारण था। लड़के को बीजू की हालत की अहमियत का एहसास हुआ और उसने बड़े साहस से डॉक्टर से कहा, आप ऑपरेशन करें, मैं तैयार हूं। लड़के का ऐसा साहस देखकर डॉक्टर हैरान रह गए और ऑपरेशन के बाद कहा ब्रेव एंड डेयरिंग बॉय।

1926 वह महात्मा गांधी से मिलने कटक स्वराज आश्रम पहुंचे। जैसे ही भीड़ आगे बढ़ी, पुलिस की फायरिंग उनकी पीठ पर पड़ी, उस दिन पुलिस के ऐसे क्रूर व्यवहार से उनकी आत्मा इतनी आहत हुई कि उन्होंने विरोध का रास्ता ढूंढ़ना शुरू कर दिया। मनमाने ने वादा किया कि जब वह बड़ा होगा तो इतना दुखी होगा कि पुलिस उसकी प्रशंसा करेगी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गोरा परिवार को जापानी सेना से सफलतापूर्वक छुड़ाने में सतकु सात उनकी बहादुरी से प्रभावित हुए और तत्कालीन वायसराय की पत्नी ने उन्हें पदक देकर सम्मानित किया। एक बार उत्कलमणि गोपबंधु दास नाव में राहत सामग्री लेकर कनिका घाटी जा रहे थे। उनके साथ 12 वर्षीय बालक बीजू पटनायक और कुछ अन्य स्वयंसेवक भी थे। बीच में गोपबन्धु वाला छाता लापरवाही से नाव से पानी में गिर गया। लड़का बीजू, कटिंग में कूद गया और छाता उठा लिया। पंडित गोपबंधु और अन्य लोग आश्चर्य से नाई को देखते हैं। उन्होंने उनकी चिंता को देखते हुए कहा- यह छाता कोई साधारण छाता नहीं है, यह आपका छाता है। इस छत्र के साथ उड़िया की सेवा और त्याग की संस्कृति जुड़ी हुई है। तो वह छाता मेरी आंखों के सामने तैर जाएगा, मैं चुपचाप कैसे देख सकता हूं?

जिस दिन किला मैदान में उतरने वाले विमान को छूने गये तो गोरा साहब ने उनकी पिटाई कर दी, उस दिन उन पर विमान स्वयं उड़ाने का जुनून सवार हो गया। इसलिए एक आशाजनक प्रयास के साथ, उन्होंने वैमानिकी इंजीनियरिंग का अध्ययन किया और एक बदकिस्मत विमान चालक के रूप में उड़ान भरी और एक के बाद एक इतिहास रचा। 23 जुलाई 1942 बरसाती सुबह। उनका डकोटा विमान कलकत्ता हवाई अड्डे से उड़ान भरने के लिए तैयार है। आसमान में लुकाछिपी का खेल चल रहा है. हवा की गति धीरे-धीरे बढ़ती है। किसी ने पायलट को सावधान करने के लिए कहा कि तूफ़ान बहुत तेज़ गति से आ रहा है। उड़ान भरने से पहले जब विमान तूफान के ऊपर से गुजरा तो उसके मुंह से निकल गया मुखबिर। फिर उसने एक विमान लिया और आकाश की चोटी तक उड़ गया। आमतौर पर जब पक्षियों को तूफान की सूचना मिलती है तो वे सुरक्षित स्थान की ओर उड़ जाते हैं। लेकिन यह जानते हुए भी कि तूफ़ान आने वाला है, बाज निडर होकर ही आकाश में उड़ सकता है। तूफ़ान की गति जितनी तेज़ होती है, चील उतनी ही ऊपर उठती है। उस दिन उनका डकोटा विमान तूफ़ानी हवाओं में उड़कर कलकत्ता से जावा के लिए उड़ गया। वहां डच सेना की नज़र दो इंडोनेशियाई तुंग नेताओं, सनत हत्तारिन और मोहम्मद हत्ता पर पड़ी और वे उन्हें नई दिल्ली ले आये। ऐसे साहसी कार्य के लिए उन्हें इंडोनेशिया का सर्वोच्च पुरस्कार 'भूमि पुत्र' की उपाधि मिली। वह प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की चिंताओं को दूर करते हुए अशांत कश्मीर घाटी में युद्धक विमान उतारने वाले पहले भारतीय थे। बिजूबाबू ओडियन भावना के प्रतीक थे। उनका महत्वाकांक्षी सपना ओडिशा का विकास था। इसकी रूपरेखा बताते हुए उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य राज्य के हर व्यक्ति के सिर पर अच्छी छत, हर परिवार को पीने का पानी, हर बच्चे के लिए अच्छा स्कूल और सभी के लिए मुफ्त अच्छी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। इसके अलावा वह अपनी उपलब्धियों को लेकर दुनिया में अपनी एक अलग पहचान स्थापित करना चाहते थे। इतना बड़ा सपना देखने के लक्ष्य के साथ वह रवीन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों को याद करते हुए कहते हैं- 'जब भी सपना देखो तो बड़ा सपना देखो। 'बड़े सपने देखकर ही बड़े काम किए जा सकते हैं।

ऐसे योग-जनित पुरुष का जन्म होता है, जो अपने असाधारण व्यक्तित्व से इतिहास रचता है, इतिहास बदलता है और उत्तरी मानव की आँखों में इतिहास बनाने के अधूरे सपने भर देता है। इतिहास को उनकी उपलब्धियों को याद रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

बीजू पटनायक को भारत रत्न प्राप्त मांग की जा रहा है। दुःखद बात है को ईसी मांग को केंद्र सरकार ने सामान्य रूप से लिया। बिजुबाबू भारत रत्न की हक़दार।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023